RNI No. : TNHIN/2013/5252 ▪ वर्ष - 13 ▪ अंक - 205 ▪ पृष्ठ - 8 ▪ रु. 5/- चेन्नई » शनिवार » 21-02-2026 ▪ www.dakshinbharat.com ▪ Email : chennai@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

5 बागलकोट में पत्थरबाजी अल्पसंख्यक तुष्टिकरण ही मुख्य कारण है : रविकुमार

6 डिजिटल युग में मातृभाषाओं को बचाना बड़ी चुनौती

7 क्या द वार्डरोब में दिव्या अग्रवाल निभा रही हैं भूत का किरदार?

हिंदी को बढ़ावा मिलने पर अन्य सभी भाषाएं मजबूत होती हैं : अमित शाह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अगरतला/भाषा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि जब हिंदी को बढ़ावा दिया जाता है, तो अन्य सभी भाषाएं भी मजबूत होती हैं। उन्होंने यहां राजभाषा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह दुष्प्रचार किया जा रहा था कि हिंदी लोगों पर थोपी जा रही है लेकिन पिछले 10 वर्षों में यह बात गलत साबित हुई है। उन्होंने कहा, ''हिंदी और अन्य स्थानीय भाषाओं के बीच कोई विवाद नहीं हो सकता क्योंकि वे एक ही मां की दो बेटियां हैं, जिन्होंने साथ-साथ प्रगति की हैं।''

■ देश में अनेक भाषाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी लिपि है, लेकिन कई बोलियां ऐसी भी हैं जिनकी अपनी कोई लिपि नहीं है। इन बोलियों को भी संरक्षित और संग्रहित किया जाना चाहिए।

शाह ने कहा, ''यह भी दुष्प्रचार किया गया कि यदि हम अपनी भाषाओं को बढ़ावा देंगे, तो हम विकास में पिछड़ जाएंगे, अनुसंधान में पिछड़ जाएंगे और दुनिया में अलग-थलग पड़ जाएंगे। चाहे जर्मनी हो, जापान हो, दक्षिण कोरिया हो, फ्रांस हो, रूस हो या चीन, इन सभी देशों ने अपनी-अपनी भाषाओं में प्रगति की है। आज ये सभी देश विकास में अग्रणी माने जाते हैं।''

शाह ने कहा कि लिपि और भाषा विवाद का मुद्दा नहीं हो सकतीं। उन्होंने कहा, ''त्रिपुरा में एक अलग मांग की गई है। मेरी अपील है कि देवनागरी लिपि को अपनाया जाए क्योंकि पूर्वोत्तर के ज्यादातर लोग इसे अपनी स्थानीय भाषा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। लोग विदेशी लिपि को अपनाकर अपनी भाषा, संस्कृति और परंपरा को कैसे संरक्षित कर सकते हैं?''

भाजपा की सहयोगी टिपरा मोथा पार्टी की मांग रही है कि राज्य की आदिवासी आबादी द्वारा बोली जाने वाली कोकबोरोक भाषा के लिए केवल रोमन लिपि का ही प्रयोग किया जाए। अब तक इस भाषा के लिए बांग्ला और रोमन दोनों लिपियों का प्रयोग किया जाता रहा है।

शाह ने कहा, ''देश में अनेक भाषाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी लिपि है, लेकिन कई बोलियां ऐसी भी हैं जिनकी अपनी कोई लिपि नहीं है। इन बोलियों को भी संरक्षित और संग्रहित किया जाना चाहिए। यदि इन बोलियों को संरक्षित करना है, तो इनके लिए एक सामान्य लिपि का निर्माण आवश्यक होगा, और इसी कारण देवनागरी लिपि अपनाने की आवश्यकता है।'' उन्होंने कहा कि देवनागरी एक कंप्यूटर-अनुकूल लिपि होने के साथ-साथ सबसे वैज्ञानिक लिपि भी है।

शिवाजी जयंती शोभायात्रा के दौरान पथराव

बागलकोट में तनाव की स्थिति, निषेधाज्ञा लागू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बागलकोट। मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी की जयंती पर निकाली गई एक शोभायात्रा पर कथित तौर पर पथराव किये जाने के बाद कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह जानकारी अधिकारियों ने शुक्रवार को दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना बृहस्पतिवार को पुराने शहर में उस समय घटी जब अपराह्न करीब 3:30 बजे शुरू हुई शोभायात्रा मस्जिद क्षेत्र से गुजर रही थी। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ गोयल ने बताया कि शोभायात्रा के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। उन्होंने कहा, हम सभी मौके पर मौजूद थे।

शोभायात्रा कल अपराह्न करीब 3:30 बजे शुरू हुई थी। जैसे ही शोभायात्रा मस्जिद के पास पहुंची, दूर से हमारी ओर दो पत्थर फेंके गए। एसपी के अनुसार, प्रारंभिक जानकारी और पुलिस द्वारा अब तक देखे गए वीडियो के आधार पर, एक पत्थर एक पुलिस कांस्टेबल को लगा जबकि दूसरा उनके कंधे पर गिरा।

गोयल ने कहा, ''किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। इसके बाद शोभायात्रा सुचारू रूप से आगे बढ़ती रही और माहौल शांतिपूर्ण बना रहा।'' पुलिस ने बताया कि शोभायात्रा को देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और स्थिति नियंत्रण में रही। गोयल ने कहा, घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। हमने शोभायात्रा की रिकॉर्डिंग भी की है। हम वीडियो फुटेज खंगाल रहे हैं। इसमें लिप्त पाये गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत बागलकोट के कुछ हिस्सों में 19 फरवरी की मध्यरात्रि से 24 फरवरी की मध्यरात्रि तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार, इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर चार से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि साथ ही खतरनाक हथियार ले जाने, सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गतिविधियों में लिप्त होने और बिना पूर्व अनुमति के सभा, समारोह या धरने आयोजित करना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपाय किए गए हैं।

फर्स्ट टेक

भारत ने विशाखापत्तनम में आईओएनएस की अध्यक्षता ग्रहण की

विशाखापत्तनम/भाषा। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने शुक्रवार को घोषणा की कि भारत ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित नौवें नौसेना प्रमुख सम्मेलन के दौरान हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (आईओएनएस) की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। उन्होंने कहा कि आईओएनएस की अध्यक्षता संभालने के साथ ही भारत समुद्री क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिक जिम्मेदारी लेने को तैयार है। सोबती ने संवाददाताओं से कहा, ''यहां आयोजित हो रहे नौवें नौसेना प्रमुख सम्मेलन के दौरान भारत ने हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है।'' उन्होंने रेखांकित किया कि समुद्री चुनौतियां सभी देशों में समान हैं और इसके लिए हिंद महासागर क्षेत्र की नौसेनाओं के बीच बेहतर अंतरसंचालन, संरचित संचार तंत्र और समन्वित प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता है।

अमेरिका में 57 वर्षीय सिख व्यक्ति का अपहरण

न्यूयॉर्क/भाषा। कैलिफोर्निया के सैन जोकिन काउंटी के ट्रेसी इलाके से 57 वर्षीय सिख व्यक्ति का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया है। सैन जोकिन काउंटी शेरिफ कार्यालय ने 'फेसबुक' पर किए गए पोस्ट में पीड़ित की पहचान अवतार सिंह के रूप में की है, जिनकी लंबाई पांच फुट सात इंच है और वजन लगभग 200 पाउंड है। घटना के समय उन्होंने हल्के रंग के पारंपरिक सिख वस्त्र पहने हुए थे। पुलिस ने बताया कि निगरानी फुटेज में मंगलवार को अपराह्न लगभग ढाई बजे (स्थानीय समयानुसार) सिंह को गहरे रंग के कपड़े पहने तीन अज्ञात व्यक्ति एक सफेद एसयूवी में बिठाते हुए दिख रहे हैं।

किम ने उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था की सराहना की

सियोल/एपी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपनी पार्टी के अहम सम्मेलन की शुरुआत करते हुए देश की अर्थव्यवस्था में हो रहे सुधार और क्षेत्रीय स्थिति की प्रशंसा की। उम्मीद की है कि किम इस सम्मेलन में अगले पांच वर्षों के लिए घरेलू और विदेश नीति का एजेंडा तय करेंगे और अपने परिवार के शासन को और मजबूत करेंगे। उत्तर कोरिया की आधिकारिक 'कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी' (केसीएनए) ने शुक्रवार को कहा कि सत्तारूढ़ 'वर्कर्स पार्टी कांग्रेस' की शुरुआत एक दिन पहले किम के अभिभाषण से हुई थी जिसमें उन्होंने अर्थव्यवस्था पर जोर दिया था।

डीवीएसी रिश्वत मामले में तमिलनाडु के मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करे : मद्रास उच्च न्यायालय

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी निदेशालय (डीवीएसी) को नगर प्रशासन और जल आपूर्ति विभाग में कथित रिश्वतखोरी के मामले में मौजूदा मंत्री के एन नेहरू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की पीठ ने कहा कि डीवीएसी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए। पीठ ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि यद्यपि ईडी की शिकायत अस्पष्ट थी, लेकिन उसने प्रचुर मात्रा में ऐसी सामग्री प्रस्तुत की जो प्रथम दृष्टया आरोप के सत्य होने का संकेत देती है। अदालत ने कहा कि बीएनएसएस की धारा 173 के तहत सरकार द्वारा 14 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच की जा सकती थी, लेकिन उसने इसमें केवल देरी की है।

एमओयू

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान राज्य सरकार और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एनआईईएलआईटी) के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर के समय, एनआईईएलआईटी के महानिदेशक मदन मोहन त्रिपाठी और अन्य अधिकारियों के साथ।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर जल्द हस्ताक्षर होंगे : अमेरिकी राजदूत

नई दिल्ली/भाषा। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने शुक्रवार को दावा किया कि नयी दिल्ली ने मॉस्को से तेल खरीदने के संबंध में वाशिंगटन के समक्ष प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने संकेत दिया कि भारत को वेनेजुएला का तेल बेचने को लेकर अमेरिका उसके साथ 'सक्रिय बातचीत' कर रहा है। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर ''बहुत जल्द'' हस्ताक्षर किए जाएंगे। उन्होंने ये टिप्पणियां अगले सप्ताह वाशिंगटन की भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल की यात्रा से पहले की गई हैं। अमेरिकी राजदूत ने नयी दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट-2026 से इतर संवाददाताओं से बातचीत में घोषणा की कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो अगले कुछ महीनों में भारत की यात्रा करेंगे और यह यात्रा 'क्वाड' ढांचे के तहत होने वाली गतिविधियों सहित कई पहलों पर चर्चा करने का अवसर होगी।

भारत समेत अपने सहयोगियों के साथ गठबंधन मजबूत कर रहा इजराइल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

यरुशलम/भाषा। भारत को ''बेहद शक्तिशाली'' बताते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका देश अपने सहयोगियों के साथ ''गठबंधन मजबूत कर रहा है।'' उन्होंने अगले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रस्तावित यरुशलम यात्रा का उल्लेख करते हुए यह बात कही।

प्रधानमंत्री मोदी के 25 फरवरी को दो दिवसीय दौरे पर इजराइल पहुंचने की उम्मीद है, जिस दौरान वह संभवतः नेसेट (संसद) को संबोधित करेंगे तथा नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात करेंगे।

नेतन्याहू ने बृहस्पतिवार को यरुशलम से लगभग 190 किलोमीटर दक्षिण में स्थित बहाद 1 (आईडीएफ अधिकारी स्कूल) में इजराइल रक्षा बलों (आईडीएफ) के कैडेट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही।

नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल बुराई के खिलाफ ''निवारक उपाय'' करता है और इसलिए, क्षेत्र में खतरों को बेअसर करने के लिए, आवश्यकतानुसार, समय-समय पर कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा, हम अपने सहयोगियों के साथ गठबंधन को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाएंगे। अगले सप्ताह एक बेहद शक्तिशाली देश के प्रधानमंत्री, इजराइल का दौरा करेंगे।'' उन्होंने कहा, ''और निश्चित रूप से, आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले मैं एक और महत्वपूर्ण दौरे से लौटा हूं, जो राष्ट्रपति (डोनाल्ड) ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने के बाद से सातवां दौरा था, जहां मैंने इजराइल के सबसे पक्के मित्र - अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की।''

सूर्यास्त	सूर्योदय
21-02-2026 6:16 बजे	22-02-2026 6:28 बजे

BSE	NSE
82,814.71 (+316.57)	25,571.25 (+116.90)

सोना	चांदी
16,203 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम	255,000 रु. प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

भारत नीति

हम नहीं समर्थक हिंसा के,
आदर्श हमारे रहे बुद्ध।
हैं विश्व शांति के हम प्रहरी,
मन वचन कर्म से सदा शुद्ध।
जो मानवता पर घात करे,
उन दुष्टों पर ही हुए क्रुद्ध।
योद्धा हैं सबल शक्ति से युत,
पर नहीं चाहते कभी युद्ध।।

ट्रंप ने 'यूएफओ' से जुड़ी फाइलें जारी करने का निर्देश दिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

वॉशिंगटन/एपी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह पेंटागन और अन्य सरकारी एजेंसियों को परग्रही जीवों (एलियन्स) और 'यूएफओ' से संबंधित फाइल की पहचान करके उन्हें सार्वजनिक करने का निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि इन विषयों में लोगों की ''गहरी रुचि है। ट्रंप ने यह घोषणा एक सोशल मीडिया पोस्ट में की। कुछ घंटे पहले ही उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर हाल में एक पॉडकास्ट साक्षात्कार में परग्रही जीवों के वास्तव में होने का संकेत देकर गोपनीय जानकारी उजागर करने का आरोप लगाया था। 'एयर फोर्स वन' विमान में संवाददाताओं से बातचीत में ट्रंप ने कहा, मुझे नहीं पता कि परग्रही जीव वास्तव में हैं या नहीं। उन्होंने ओबामा के संदर्भ में कहा, मैं गोपनीयता हटाकर शायद उन्हें मुसीबत से बाहर निकाल दूं। अपने सोशल मीडिया मंच पर एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि वह एजेंसियों को एलियन और बाह्य-स्थलीय जीवन, अज्ञात हवाई घटनाएं (यूएपी), अज्ञात उड़न तश्तरियों (यूएफओ) और इन अत्यंत जटिल लेकिन बेहद रोचक और महत्वपूर्ण मामलों से जुड़ी सभी सूचनाएं जारी करने का निर्देश दे रहे हैं।

ओबामा ने सप्ताहांत में एक पॉडकास्ट में अपनी टिप्पणी के बाद स्पष्ट किया था कि उन्होंने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं देखा है कि परग्रही जीव हमारे संपर्क में आए हैं।

अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने ट्रंप के व्यापक शुल्क वृद्धि के आदेशों को रद्द किया

वाशिंगटन/एपी। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई देशों के खिलाफ लगाए गए व्यापक शुल्क वृद्धि के आदेशों को रद्द कर दिया। इससे ट्रंप प्रशासन के आर्थिक एजेंडे को बड़ा झटका लगा है।

यह निर्णय आपातकालीन शक्तियों से संबंधित कानून के तहत लगाए गए शुल्कों पर केंद्रित है, जिसमें लगभग हर दूसरे देश पर लगाए गए व्यापक ''पारस्परिक'' शुल्क भी शामिल हैं।

यह ट्रंप के व्यापक एजेंडे का पहला प्रमुख हिस्सा है, जो सीधे तौर पर देश की शीर्ष अदालत के सामने आया है, जिसे उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में तीन रूढ़िवादी न्यायाधीशों की नियुक्तियों के माध्यम से आकार देने में मदद की थी।

राजनाथ सिंह ने 'मिलन' में वैश्विक नौसैनिक सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

विशाखापत्तनम/भाषा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि वे समुद्री क्षेत्र में लगातार जटिल और परस्पर संबद्ध चुनौतियों का आपसी सम्मान और सहयोग की भावना से प्रेरित होकर समाधान करने के लिए सामूहिक रूप से काम करें।

बृहस्पतिवार को यहां 'अभ्यास मिलन' के उद्घाटन समारोह के दौरान 74 देशों के नौसेना प्रमुखों और प्रतिनिधिमंडलों को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि जल दस्यु, समुद्री आतंकवाद, अवैध रूप से मछली पकड़ने, तस्करी जैसे पारंपरिक खतरे के साथ साथ अब साइबर खतरे और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान जैसी उभरती हुई चुनौतियां भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता बढ़ा रहा है जिससे मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान दिनों दिन अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो रहे हैं।

कल रात जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में सिंह के हवाले से कहा गया है, ''अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापना में नौसेनाओं की भूमिका समय के साथ बढ़ती ही गई है। पिछले कुछ दशकों में तीव्र आर्थिक विकास हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय व्यापार और परिवहन में भारी वृद्धि हुई है। जलडमरूमध्य और जलमार्गों पर स्वामित्व के लिए प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है, जिससे कभी-कभी संघर्ष की आशंका भी पैदा हो जाती है।'' उन्होंने कहा कि जलमग्न संसाधनों, विशेषकर दुर्लभ खनिजों पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान बढ़ने से तनाव में एक नया आयाम जुड़ रहा है।

सिंह ने देशों और क्षेत्रों में फैल रही आतंकवादी गतिविधियों से जलक्षेत्रों की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी नौसेना चाहे कितनी भी सक्षम क्यों न हो, वह उभरती चुनौतियों का अकेले सामना नहीं कर सकती। उन्होंने एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए नौसेनाओं के बीच बेहतर सहयोग के महत्व पर बल दिया।

केंद्रीय मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र से संबंधित मामलों के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) द्वारा प्रदान किए गए मजबूत कानूनी ढांचे पर प्रकाश डाला जिसे एक व्यापक वैश्विक नौसेना संरचना के माध्यम से और मजबूत किया जा सकता है।

एआई, जैविक बुद्धिमत्ता के मेल से बदल सकता है स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्यः मजूमदार-शॉ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। जैव-प्रौद्योगिकी कंपनी बायोकॉन की कार्यकारी चेयरपर्सन किरण मजूमदार-शॉ ने शुक्रवार को कहा कि जैविक बुद्धिमत्ता और कृत्रिम मेधा (एआई) का मेल चिकित्सा क्षेत्र में बड़े बदलाव ला सकता है, जिससे भविष्य की बीमारियों का पहले ही अनुमान लगाने, पुनर्निर्माण विज्ञान और जीवनकाल प्रबंधन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति संभव होगी।

किरण मजूमदार-शॉ ने यहां आयोजित 'एआई इम्पैक्ट समिट' को संबोधित करते हुए कहा, जीव-विज्ञान अपने आप में गहरी समझ विकसित करने में सीमित था, लेकिन एआई उपकरण जीवित प्रणालियों को समझने के लिए असीमित अवसर खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैविक प्रणालियां 'विभक्त डेटा सेंटर' की तरह काम करती हैं, जो गीगावाट बिजली से चलने वाले एआई प्रणाली की तुलना में बहुत कम ऊर्जा में जानकारी का विश्लेषण करती हैं।

उन्होंने कहा, जीव विज्ञान से एआई को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है जैसे कि कम ऊर्जा में काम कैसे करें, तेजी से कैसे काम करें और अलग-अलग तरह के डेटा का तुरंत विश्लेषण कैसे करें। उन्होंने बताया कि एआई और जीव विज्ञान का संगम एक शक्तिशाली परिवर्तनकारी प्रक्रिया होगी और भारत इस वैश्विक बदलाव का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

उन्होंने कहा कि एआई क्षतिग्रस्त ऊतकों और अंगों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण पर केंद्रित पुनर्योजी विज्ञान को गति दे सकती है और स्वास्थ्य सेवाओं को अस्पताल-केंद्रित मॉडल से हटाकर पूर्वानुमानात्मक एवं निवारक सामुदायिक देखभाल की ओर ले जाने में मदद कर सकती है।

डीएनए में निहित पीढ़ीगत सीख के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने प्रवासी पक्षियों की दिशात्मक बुद्धिमत्ता जैसे उदाहरणों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, एआई के बिना जीव विज्ञान की गहरी समझ हासिल करना संभव नहीं है। भविष्य इसी संगम से परिभाषित होगा।

एआई समिट में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया, 10 लोग हिरासत में लिए गए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को 'एआई इम्पैक्ट समिट' के आयोजन स्थल पर पहुंचकर अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए, जिसके बाद पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में ले लिया। भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्य विपक्षी दल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल की है।

युवा कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं के इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि 'एआई इम्पैक्ट समिट' के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन इस आयोजन के खिलाफ नहीं, बल्कि अमेरिका के साथ हुए अंतरिम व्यापार समझौते के खिलाफ था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 'एआई इम्पैक्ट समिट' में विरोध प्रदर्शन के दौरान लगभग 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा, उन्हें तुरंत हटा दिया गया और तिलक मार्ग पुलिस थाने ले जाया गया। कानून-व्यवस्था की स्थिति को भंग करने की किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। युवा कांग्रेस से जुड़े प्रदर्शनकारी हॉल नंबर-5 के अंदर मार्च करते हुए पहुंचे। वे सफेद टी-शर्ट पहने या पकड़े हुए थे, जिन पर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें छपी थीं, तथा उन पर इंडिया यूएस ट्रेड डील, एपस्टीन फाइल्स और पीएम इज़ कम्प्रोमाइज्ड (प्रधानमंत्री झुक गए) जैसे नारे लिखे थे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने टी-शर्ट भी उतार दी। उनके विरोध प्रदर्शन के चलते वहां अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद कुछ प्रतिभागियों और कुछ प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। पुलिस का कहना है कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कृष्णा हरि भी शामिल हैं। मौके पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद हॉल के अंदर सुरक्षा और कड़ी की जाएगी। यह विरोध प्रदर्शन कुछ ही मिनटों तक चला, जिसके बाद समूह को हॉल से बाहर निकाल दिया गया। इस घटना ने अतिथियों और अन्य आगंतुकों को हैरान कर दिया, क्योंकि 'एआई इम्पैक्ट समिट' के मद्देनजर यह अप्रत्याशित था।

एआई से वैश्विक वृद्धि 0.8% बढ़ेगी, नौकरियों के लिए उच्च जोखिम भी मौजूद : आईएमएफ प्रमुख

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने शुक्रवार को कहा कि कृत्रिम मेधा (एआई) वैश्विक आर्थिक वृद्धि को 0.8 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है और भारत के 'विकसित भारत' बनने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकती है।

हालांकि, जॉर्जीवा ने चेतावनी भी दी कि एआई से नौकरियां कम होने और वित्तीय स्थिरता पर जोखिम भी उत्पन्न हो सकते हैं।

जॉर्जीवा ने यहां आयोजित 'एआई इम्पैक्ट समिट 2026' में कहा कि वह एआई को लेकर आशावादी हैं, लेकिन इसके प्रभाव को अत्यधिक सकारात्मक दिखाने से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एआई को अच्छाई की ताकत या बुराई की ताकत के रूप में इस्तेमाल किए जाने के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

जॉर्जीवा ने कहा, एआई वैश्विक आर्थिक वृद्धि को लगभग एक प्रतिशत अंक तक बढ़ा सकता है। हमारा अनुमान 0.8 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था कोविड महामारी से पहले की तुलना में तेजी से बढ़ेगी। यह नए अवसर और अधिक रोजगार सृजित करने के लिए शानदार है। भारत के लिए भी यही प्रभाव दिख रहा है और इसका अर्थ है कि भारत का विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एआई उन देशों के लिए अधिक अवसर पैदा करता है जो डिजिटल बुनियादी ढांचा, कौशल विकास और एआई को तेजी से अपनाने में आगे हैं। उन्होंने कहा कि देशों को जोखिमों के प्रति सचेत रहते हुए अवसरों को अपनाना चाहिए। उन्होंने एआई से जुड़े तीन प्रमुख जोखिमों को गिनाते हुए कहा, मैं एआई को लेकर बहुत आशावादी हूं। हालांकि मैं बहुत भोली भी नहीं हूं, इससे काफी जोखिम भी जुड़े हैं।

जॉर्जीवा ने कहा कि सबसे पहले, एआई से कुछ देशों के पास प्रौद्योगिकी होने और कुछ देशों के पास न होने के कारण वैश्विक असमानता बढ़ने का खतरा है। दूसरा, यह वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम पैदा कर सकता है, क्योंकि एआई अनियंत्रित होने पर वित्तीय बाजारों में संकट पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, एआई आने से नौकरियों के जाने का भी खतरा है, और अभी तक ऐसी सोच नहीं बन पाई है कि लोग नई एआई अर्थव्यवस्था में अपनी जगह किस तरह बना सकेंगे।

एआई में प्रशिक्षण के लिए आंध्र प्रदेश की आईबीएम के साथ साझेदारी

नई दिल्ली/ अमरावती/ भाषा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी आईबीएम के साथ एक साझेदारी की घोषणा की, जिसके तहत राज्य के एक लाख युवाओं को कृत्रिम मेधा (एआई), साइबर सुरक्षा और क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रशिक्षित किया जाएगा।

नायडू ने कहा कि इस पहल से शिक्षार्थियों को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप कौशल प्राप्त होगा, जिससे आंध्र प्रदेश के उभरते प्रौद्योगिकी कार्यबल को मजबूती मिलेगी। राजधानी में आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि शुक्रवार को ही आईबीएम की वरिष्ठ उपाध्यक्ष एना पाउला और अन्य अधिकारियों के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। नायडू ने कहा, हम आंध्र प्रदेश के एक लाख प्रतिभाशाली युवाओं को एआई, साइबर सुरक्षा और क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रशिक्षित करने के लिए आईबीएम के साथ साझेदारी कर रहे हैं।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एआई सक्षम कृषि परिवेश की वकालत की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वैश्विक निवेशकों से खेती के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) समाधानों को बढ़ाने में साझेदार बनने का शुक्रवार को आह्वान किया। साथ ही कहा कि उनका राज्य दुनिया के सबसे आधुनिक कृषि-नवाचार परिवेश में से एक बन रहा है।

'एआई इम्पैक्ट सम्मेलन' में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा, '' महाराष्ट्र आज वैश्विक स्तर पर कृषि-नवाचार के सबसे सशक्त एवं आकर्षक परिवेश में से एक पेश करता है।'' फडणवीस ने कहा कि यहां 150 लाख हेक्टेयर खेती की जमीन, अलग-अलग तरह की कृषि- जलवायु परिस्थिति, बड़े कृषि विश्वविद्यालय और एआई शोध केन्द्र, स्टार्टअप परिवेश, स्पष्ट नियामकीय ढांचा और निवेशकों के लिए एकल खिड़की सुविधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राज्य को चुनने से, साझेदार को दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को जोड़ने, खाद्य सुरक्षा एवं जलवायु सहिष्णुता के लिए मापन योग्य समाधान में निवेश करने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा, '' कृषि केवल एक आर्थिक क्षेत्र नहीं है, यह रोजी-रोटी, सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा है। भारत इसे बहुत गहराई से समझता है और हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदृष्टी नेतृत्व में भारत ने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और जिम्मेदार एआई को राष्ट्रीय विकास के केंद्र में रखा है।'' उन्होंने कहा कि एआई स्थानीय मौसम का पूर्वानुमान, कीटों के फैलने की शुरुआती चेतावनी, सटीकता, सिंचाई एवं उर्वरकों के बारे में दिशानिर्देश दे सकता है।

एसआईआर प्रक्रिया के बाद गुजरात, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के मतदाताओं की संख्या करीब 69 लाख घटी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के बाद गुजरात, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में मतदाताओं की संख्या में लगभग 69 लाख की कमी आई है। निर्वाचन आयोग द्वारा शुक्रवार को साझा किए गए आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है। गुजरात, लक्षद्वीप और पुडुचेरी ने हाल ही में एसआईआर की प्रक्रिया के बाद अपनी-अपनी अंतिम मतदाता सूचियां प्रकाशित की हैं।

निर्वाचन आयोग के मुताबिक पिछले साल 27 अक्टूबर को एसआईआर प्रक्रिया कराने की की घोषणा से पहले, गुजरात और दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मतदाताओं की संख्या 5.19 करोड़ थी। अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद, उनकी कुल मतदाता संख्या घटकर 4.50 करोड़ रह गई यानी मतदाताओं की संख्या में 68.9 लाख की कमी आई है। गुजरात में एसआईआर से पहले कुल मतदाताओं की संख्या 5.08 करोड़ थी, जो घटकर 4.40 करोड़ रह गई। मतदाताओं की संख्या में 68.12 लाख की कमी आई है जो कुल वोटरों का 13.40% है। लक्षद्वीप में मतदाता सूची की शुद्धिकरण प्रक्रिया से पहले मतदाताओं की संख्या 57,813 थी। अंतिम मतदाता सूची में यह संख्या घटकर 57,607 रह गई। इस प्रकार कुल मतदाताओं की संख्या में 0.36% यानी 206 मतदाताओं की कमी आई है। चुनाव वाले केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में एसआईआर शुरू होने से पहले 10.21 लाख मतदाता पंजीकृत थे जबकि अंतिम सूची में यह संख्या घटकर 9.44 लाख रह गई।

जम्मू कश्मीर सरकार इस साल 30 हजार रिक्त पदों को भरेगी : उमर अब्दुल्ला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जम्मू/भाषा। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को दोहराया कि उनकी सरकार समयबद्ध तरीके से रिक्त पदों को भरने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ उन्होंने इस साल 30 हजार से अधिक रिक्त पदों को भरने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री जम्मू-कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान सदस्य प्रोफेसर घरू राम भगत द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने सदन को सूचित किया कि सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, इस्तीफे और अन्य प्रशासनिक कारणों से विभिन्न सरकारी विभागों में समय-समय पर रिक्तियां उत्पन्न होती रहती हैं।

अब्दुल्ला ने कहा, ''रिक्तियों के समय-समय पर मूल्यांकन और वैधानिक प्रावधानों के अनुसार संबंधित भर्ती एजेंसियों को समय पर जानकारी भेजने के लिए संस्थागत तंत्र मौजूद हैं।'' उन्होंने कहा कि सरकार ने रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कई उपाय किए हैं।

सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सात उपायों की घोषणा की

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने देश के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुक्रवार को सात उपायों की घोषणा की जिनमें ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए ऋण सहायता एवं वैकल्पिक व्यापार साधनों को समर्थन शामिल है।

ये उपाय 25,060 करोड़ रुपए के निर्यात प्रोत्साहन मिशन का हिस्सा हैं। इस मिशन के 10 में से तीन घटकों को जनवरी में पहले ही लागू किया जा चुका है।

डिजिटल माध्यम से निर्यात करने वालों को समर्थन देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने ब्याज अनुदान एवं आंशिक ऋण गारंटी के साथ ऋण सुविधाएं शुरू करने की घोषणा की है।

'डायरेक्ट ई-कॉमर्स क्रेडिट' सुविधा के तहत 50 लाख रुपए तक सहायता 90 प्रतिशत गारंटी कवरेज के साथ उपलब्ध होगी। 'ओवरसीज इन्वेंटरी क्रेडिट' सुविधा के अंतर्गत पांच करोड़ रुपए तक सहायता 75 प्रतिशत गारंटी कवरेज के साथ दी जाएगी।

कांग्रेस डरने वाली नहीं, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाती रहेगी: उमंग सिंघार

भोपाल/भाषा। मध्यप्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा विधानसभा में आपत्तिजनक शब्द कहे जाने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को उठाती रहेगी और डरने वाली नहीं है। सिंघार ने कहा कि कांग्रेस बिजली दरों, आदिवासियों की जमीन, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी।

विधानसभा में बृहस्पतिवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान विजयवर्गीय ने सिंघार के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था, जिससे सदन में हंगामा हो गया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खेद जताया था। सिंघार ने विधानसभा परिसर में संवाददाताओं से कहा, ''विपक्ष के रूप में कांग्रेस जनता की आवाज है। अगर पार्टी के विधायक मुद्दे उठाते हैं तो वे आम लोगों की बात करते हैं। मैंने भी कल (बृहस्पतिवार को) राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रदेश के हित और जनता की आवाज उठाई थी।'' उन्होंने कहा, ''अगर प्रदेश में सस्ती बिजली मिले, तो यह जनता की मांग है तो फिर मंत्री किसे 'औकात' दिखा रहे हैं? क्या वे बिजली उपभोक्ताओं को उनकी जगह बता रहे हैं या फिर सिंगरौली में अदाणी की खदान के लिए जंगल कटने से विस्थापित हो रहे आदिवासियों को उनकी जगह दिखा रहे हैं?''

जल संरक्षण को स्थायी और प्रभावी बनाने के लिए जनभागीदारी अनिवार्य : मुख्यमंत्री साय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

रायपुर/भाषा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को कहा कि जल संकट 21वीं सदी की केवल गंभीर पर्यावरणीय ही नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और विकासात्मक चुनौती बन चुका है इसलिए जल संरक्षण को स्थायी व प्रभावी बनाने के लिए जनभागीदारी अनिवार्य है।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री साय और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की संयुक्त अध्यक्षता में शुक्रवार को नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई बैठक में राज्य में 'जल संचय-जनभागीदारी 2.0' अभियान के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री पाटिल इस बैठक में डिजिटल रूप से शामिल हुए और बैठक को संबोधित किया।

इस दौरान बिलासपुर, दुर्ग और सूरजपुर जिले के कलेक्टरों ने अपने-अपने जिलों में अभियान के अंतर्गत संचालित कार्यों व गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी।

साय ने इस दौरान कहा कि जल संकट 21वीं सदी की केवल गंभीर पर्यावरणीय ही नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और विकासात्मक चुनौती भी बन चुका है इसलिए जल संरक्षण को स्थायी व प्रभावी बनाने के लिए जनभागीदारी अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर राज्य सरकार जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रतिबद्ध है।

साय ने कहा कि अभियान के पहले चरण में छत्तीसगढ़ ने देशभर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया और विभिन्न जिलों को भी अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार मिले।

पहले चरण में सामुदायिक भागीदारी के मॉडल पर कार्य करते हुए बड़े पैमाने पर बोरवेल पुनर्भरण, छत पर वर्षा जल संचयन जैसी संरचनाओं का निर्माण किया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 की तुलना में 2025 में पांच ब्लॉकों में भू-जल निकासी में कमी और भू-जल स्तर में सुधार दर्ज किया गया, जो जल संरक्षण प्रयासों के सकारात्मक परिणामों का संकेत है।

सत्ताधारी दल और विपक्षी दलों के सहयोग से लोकतंत्र मजबूत होता है : हरियाणा के राज्यपाल

चंडीगढ़/भाषा। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने शुक्रवार को कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सत्ता पक्ष और विपक्षी दल संविधान का अक्षरशः पालन करते हैं और उसकी भावना के अनुरूप मिलकर काम करते हैं। राज्यपाल ने बजट सत्र के पहले दिन राज्य विधानसभा को संबोधित करते हुए विचारों की विविधता को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बताया।

घोष ने कहा, यह सदन जनता की आवाज है और सरकार का यह दायित्व है कि वह ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ उस आवाज को परिणामों में परिवर्तित करे। उन्होंने कहा, लोकतंत्र तभी सही मायने में मजबूत होता है जब सत्ता पक्ष और विपक्षी दल संविधान का अक्षरशः पालन करते हैं और उसकी भावना के अनुरूप मिलकर काम करते हैं।'' राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि सत्र के दौरान होने वाली चर्चाएं रचनात्मक होंगी। उन्होंने कहा कि वह सदन द्वारा संवाद और आम सहमति के माध्यम से ऐतिहासिक निर्णय लिए जाने की आशा करते हैं। घोष ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार सत्ता को जनसेवा का एक साधन मानती है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से निर्देशित सुशासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

व्यापार समझौते बाजार पहुंच में सुधार से निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका : आरबीआई लेख

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर वार्ता पूरी होने और अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौता होने से आने वाले वर्षों में भारत की बाजार पहुंच में सुधार और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में मदद मिलने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को एक बुलेटिन में यह बात कही।

आरबीआई के फरवरी बुलेटिन में 'अर्थव्यवस्था की स्थिति' पर प्रकाशित एक लेख में यह भी कहा गया कि अर्थव्यवस्था के लिए निकट भविष्य का आर्थिक परिदृश्य अनुकूल बना हुआ है और यह उपभोग, निवेश और उत्पादकता बढ़ाने वाले सुधारों से प्रेरित होकर अपनी उच्च वृद्धि गति को बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में है।

बयान में कहा गया कि जनवरी के अंत तक भारत-ईयू मुक्त व्यापार वार्ता पूरी होने और उसके बाद भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौता होने से आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है।

इससे भारतीय कंपनियों को बाजार तक बेहतर पहुंच मिलेगी, उनका निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक बनेगा और वे वैश्विक व्यापार शृंखलाओं में अधिक गहराई से शामिल हो सकेंगे। इस लेख के मुताबिक, इन समझौतों से तात्कालिक प्रभाव के तौर पर निवेशकों की धारणा में बदलाव आया है।

फरवरी में इक्विटी और ऋण क्षेत्र में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश फिर से बढ़ा है।

लेख कहता है कि वित्त वर्ष-2026-27 के केंद्रीय बजट ने सरकार की वित्तीय अनुशासन के प्रति प्रतिबद्धता को फिर से रेखांकित किया है। इसके साथ ही दीर्घकालिक वृद्धि पर ध्यान बनाए रखते हुए पूंजीगत व्यय के लिए आवंटन बढ़ाया गया है।

आरबीआई बुलेटिन के मुताबिक, संशोधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) शृंखला के तहत जारी पहले आंकड़ों के हिसाब से मुख्य मुद्रास्फीति का स्तर नरम बना हुआ है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बुलेटिन के इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और आरबीआई के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
बेंगलूरु क्लासीफाइड
नाम परिवर्तन

CHANGE OF NAME

I, **P LAKSHMI** (Existing Name of as per change of NOK Service Document) legally wedded spouse of No.17006101H, NK(VM), **P DINASEKHAR,** residing at D.No.7-16,Venkatrapuram(V),Polavaram(P),Puthalpattu(M),Chittoor Dist, AP, 517124 have changed my name from **P LAKSHMI** to **GORJALA LAKSHMI** (Proposed New Name of Spouse)

विदेशी मुद्रा भंडार 8.66 अरब डॉलर बढ़कर 725.72 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 13 फरवरी को समाप्त सप्ताह में 8.66 अरब डॉलर बढ़कर 725.72 अरब डॉलर के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इससे पूर्व छह फरवरी को समाप्त सप्ताह में कुल विदेशी मुद्रा भंडार 6.71 अरब डॉलर घटकर 717.06 अरब डॉलर रह गया था। इससे पहले का सर्वोच्च स्तर जनवरी में 723.774 अरब डॉलर का रहा था। आरबीआई की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, 13 फरवरी को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा माने जाने वाली विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 3.55 अरब डॉलर बढ़कर 573.60 अरब डॉलर हो गईं। डॉलर के रूप में व्यक्त की जाने वाली विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर अमेरिकी मुद्राओं के मूल्य में घट-बढ़ के प्रभाव शामिल होते हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार का मूल्य 4.99 अरब डॉलर बढ़कर 128.46 अरब डॉलर हो गया। केंद्रीय बैंक ने बताया कि विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 10.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.92 अरब डॉलर हो गया। आंकड़ों के अनुसार, समीक्षाधीन सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास भारत का आरक्षित भंडार भी 1.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.734 अरब डॉलर हो गया।

तमिलनाडु के लोगों की तरह मैं भी आश्वस्त हूं कि दो महीने में फिर से सरकार बनाएगी द्रमुक : स्टालिन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शुक्रवार को विश्वास जताया कि प्रदेश में सत्तारूढ़ द्रमुक दो महीने के भीतर फिर से सरकार बनाएगी। प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के बाद द्रमुक दोबारा सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने कहा कि वह कई विकास परियोजनाओं को पूरी ऊर्जा के साथ शुरू करेंगे।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा, ''तमिलनाडु के लोगों की तरह, मैं आश्वस्त हूं कि द्रमुक की सरकार अगले दो महीनों में एक बार फिर से बनेगी।'' राज्य की जनता को सेवा करने का इतना शानदार अवसर देने के लिए धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त किया कि ''उन्होंने पेरियार (तर्कवादी नेता ई.वी. रामासामी), पेरारिग्नार अन्ना (पूर्व मुख्यमंत्री सी एन अन्नादुरई) और कलैगनार (दिवंगत मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि) के मार्ग पर चलते हुए एक द्रविड़ मॉडल सरकार चलाई है।'' स्टालिन ने चुनावी वर्ष के अंतिम विधानसभा सत्र के समापन के दौरान कहा, ''मुझे लगता है कि मुझे सौंपी गई जिम्मेदारी मैंने बखूबी निभाई है। मैंने महसूस किया कि मैं तमिलनाडु को और भी समृद्ध बना सकता हूं। मुझे यह अवसर देने के लिए मैं जनता का आभारी हूं।'' तमिलनाडु में एक दशक के अन्नाद्रमुक के शासन के अंत के बाद उन्होंने मई 2021 में प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। विधानसभा के संक्षिप्त सत्र के दौरान स्टालिन ने कहा कि अगले दो महीनों में जब हम वापस आएंगे तो हम निश्चित रूप से तेज गति से आगे बढ़ेंगे।

मुलाकात दक्षिण भारत राष्ट्रमत

चेन्नई में शुक्रवार को तमिलनाडु विधानसभा के आठवें सत्र की 16वीं विधानसभा के समापन के अवसर पर सचिवालय में मीडियाकर्मियों से मुलाकात कर धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन।

सिंगापुर में प्रख्यात तमिल हस्तियां 'ग्लोबल तमिल्स अवॉर्ड' से सम्मानित

सिंगापुर। इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर में रह रहे तमिल मूल के तीन व्यक्तियों तथा तमिलनाडु के एक प्राध्यापक को इस सप्ताह सिंगापुर की 74 वर्ष पुरानी एक संस्था ने दक्षिण भारतीय भाषा और संस्कृति के संवर्धन में योगदान के लिए सम्मानित किया। सिंगापुर स्थित साप्ताहिक अखबार तबला' के अनुसार, तमिल्स फेस्टिवल 2026 ग्लोबल तमिल्स अवॉर्ड्स' समारोह का आयोजन तमिल्स आर्ट्स एंड कल्चर सोसायटी' (टीएसीएस) ने स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय तमिल संगठनों के सहयोग से किया।

रिपोर्ट में कहा गया कि यह पहल अगली पीढ़ी के लिए तमिल भाषा, कला और संस्कृति को संरक्षित करने का संगठित प्रयास है। मंगलवार को आयोजित यह उत्सव मूल रूप से 1952 में तमिल मुरासु अखबार के संस्थापक तमिजवेल जी सरंगपाणी ने सामुदायिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया था। उनका निधन हो चुका है। टीएसीएस के अध्यक्ष मा. गोविंदराजू ने कहा कि इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य 1950 के दशक में सरंगपाणी द्वारा प्रोत्साहित एकता और भाईचारे की भावना को पुनर्जीवित करना है, जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर थी। समारोह में साहित्य, कला एवं प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में तमिल भाषा के लिए उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। तमिलनाडु के प्रोफेसर थमिलप्परिथि मारी को सोरकलंजिया सेम्मल' (शब्दकोश विशेषज्ञ) पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें 174 भाषाओं के वैश्विक ऑनलाइन शब्दकोश ढांचे में तमिल को 24वें से सातवें स्थान पर पहुंचाने का श्रेय दिया गया है। उन्होंने अगले तीन वर्षों में तमिल को अंग्रेजी से आगे शीर्ष स्थान पर पहुंचाने का लक्ष्य जताया। इंडोनेशिया तमिल संगम के अध्यक्ष डॉ. विसागन मैलाचलम को 'लाइफटाइम तमिल लिटरेरी अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि इंडोनेशिया में तमिल शिक्षा चार से बढ़कर 10 विद्यालयों तक पहुंच चुकी है और 2026 तक 2,000 बच्चों तक तमिल शिक्षा का ज्ञान देने का लक्ष्य है। स्विट्जरलैंड स्थित तमिल कवि और लेखक डॉ. गंगाइमगन को भी इसी श्रेणी में सम्मानित किया गया।

दक्षिण रेलवे के चेन्नई डिवीज़न में राजभाषा उत्सव का समापन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। यहां दक्षिण रेलवे के चेन्नई डिवीजन में 20 फरवरी को राजभाषा उत्सव का समापन दिवस समारोह आयोजित किया।

इसकी अध्यक्षता चेन्नई डिवीज़न के डिवीज़नल रेलवे मैनेजर शैलेंद्र सिंह ने की और इसमें अतिरिक्त मंडल रेलवे मैनेजर तेजप्रताप सिंह के साथ अन्य डिवीजनल अधिकारी उपस्थित थे। राजभाषा उत्सव के दौरान साल 2025-26 के लिए, 22 सितंबर 2025 से 28 जनवरी 2026 तक कर्मचारियों के लिए हिंदी निबंध, भाषण, नोटिंग और ड्राफ्टिंग, हिंदी बातचीत, हिंदी क्विज़, अंताक्षरी और सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन हुए, जिसमें कुल 386 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। चेन्नई डीआरएम शैलेंद्र सिंह ने डिवीज़न में राजभाषा को लागू करने को प्रोग्रेसिव बताया और राजभाषा सेक्शन को भविष्य में भी इसकी प्रोग्रेस जारी रखने का निर्देश दिया। अतिरिक्त डीआरएम व अतिरिक्त मुख्य राजभाषा अधिकारी तेज प्रताप सिंह ने अवॉर्ड पाने वालों को बधाई दी और उन्हें राजभाषा की तरक्की के लिए हिंदी में ऑफिशियल काम करने के लिए हिम्मत दी। समापन समारोह का आयोजन चेन्नई डिवीजन के राजभाषा अधिकारी एन. इंद्रजीत ने किया।

अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाला गठबंधन तमिलनाडु विस चुनाव में तीसरे स्थान पर रहेगा : कांग्रेस सांसद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

शिवकाशी। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने शुक्रवार को कहा कि तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के नेतृत्व वाला गठबंधन आगामी विधानसभा चुनावों में वोट प्रतिशत के लिहाज से तीसरे स्थान पर रहेगा। विरुधुनगर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले टैगोर ने एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा कि शिवकाशी हो या कोई अन्य क्षेत्र, अन्नाद्रमुक नीत गठबंधन तीसरे स्थान पर ही रहेगा। उन्होंने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, हमारे सर्वेक्षण से पता चलता है कि अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन को विधानसभा चुनावों में डाले गए कुल मतों का केवल 18-20 प्रतिशत ही मिलेगा। यह एक अकाट्य सत्य है।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि चुनाव लड़ने की योजना बना रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता भी अंततः हार के डर से अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेंगे।

उन्होंने कहा, इस चुनाव में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता अन्नाद्रमुक-भाजपा गठबंधन को नकार देगी। वे तीसरे स्थान पर रहेंगे। (हकीकत में) हम दो ऐसी पार्टियों की बात कर रहे हैं, जो दौड़ में भी नहीं हैं। टैगोर ने दोहराया कि वह विरुधुनगर निर्वाचन क्षेत्र से फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे।

उन्होंने कहा, विरुधुनगर के साथ मेरा प्यार और अपनेपन का रिश्ता है। मैं विरुधुनगर के लोगों के कल्याण के लिए संसद में आवाज उठाना जारी रखूंगा।

तमिलनाडु में गांजे की तस्करी के लिए अन्नाद्रमुक जिम्मेदार : मंत्री अंबरासन

चेन्नई। तमिलनाडु के मंत्री टी एम अंबरासन ने दावा किया कि राज्य में गांजे की तस्करी पिछली अन्नाद्रमुक सरकार के दौरान भी व्यापक रूप से होती रही थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरे राज्य में प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठा रही है।

टी एम अंबरासन ने बृहस्पतिवार रात एक बैठक को संबोधित करते हुए दावा किया कि उत्तरी राज्यों से हजारों लोग प्रतिदिन चेन्नई आते हैं और उनमें से कुछ लोग तमिलनाडु में थोड़ी मात्रा में गांजा लाते हैं।

उन्होंने दावा किया कि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) की पूर्व सरकार अपने कार्यकाल के दौरान गांजे की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण करने में विफल रही, जिसके कारण वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई।

अमित शाह ने स्टालिन के दोगलेपन का पर्दाफ़ाश किया

भ्रष्ट मंत्री नेहरू को हटाया जाए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। भाजपा के प्रवक्ता एएनएस प्रसाद ने स्टालिन सरकार को घेरते हुए एक विज्ञप्ति में बताया कि लोकतंत्र की रक्षा और न्याय को बनाए रखने के लिए, आज हाई कोर्ट के ऐतिहासिक और बहुत ज़रूरी फ़ैसले को देखते हुए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को इसे ईमानदारी और अच्छे विश्वास के साथ मानना चाहिए, भ्रष्टाचार को खत्म करके बेहतरीन लीडरशिप दिखानी चाहिए, और भ्रष्ट मंत्री नेहरू को तुरंत अपनी कैबिनेट से निकाल देना चाहिए।

मंत्री केएन नेहरू, जो मुख्यमंत्री स्टालिन की कैबिनेट में नगर प्रशासन और जल आपूर्ति मंत्री के तौर पर काम करते हैं, को चेन्नई हाई कोर्ट ने टेंडर में गड़बड़ी और गैर-कानूनी नियुक्तियों के ज़रिए अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करने और रिश्वत लेने के आरोप में तुरंत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुक्कोट्टई में एक आम सभा के दौरान आरोप लगाया था, द्रमुक सरकार का प्रशासन 20 प्रतिशत कमीशन वाला शासन साबित हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) ने मंत्री नेहरू पर साफ़-साफ़ आरोप लगाए हैं, जिससे शक की कोई गुंजाइश नहीं है।

मद्रास हाईकोर्ट ने दिए निर्देश: नगर प्रशासन विभाग में नियुक्ति और टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता पर हो एफआईआर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। नगर प्रशासन विभाग में नियुक्तियों और टेंडर प्रक्रियाओं में अनियमितताओं के मामले सामने आने के बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने विजिलेंस और एंटी-करप्शन विभाग को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर केस दर्ज करने का निर्देश दिया है।

न्यायालय का मानना है कि नगर प्रशासन विभाग में नियुक्तियों और टेंडर प्रक्रियाओं में अनियमितताओं के प्रथम दृष्टया प्रमाण मौजूद हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखकर मंत्री के.एन. नेहरू द्वारा तमिलनाडु नगर प्रशासन विभाग में नियुक्तियों के लिए रिश्वत लेने और टेंडरों के आवंटन में अनियमितताओं के आरोपों के संबंध में केस दर्ज करने का निर्देश दिया था। इस पत्र के आधार पर एआईएडीएमके सांसद इनबादुराई और आदिनारायणन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की थी। इन याचिकाओं की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि एक अन्य मामले की जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य डीजीपी को भेज दिए गए हैं और इस आधार पर मामले दर्ज करने के निर्देश जारी किया जाए। तमिलनाडु सरकार की ओर से यह बताया गया कि प्रवर्तन निदेशालय का पत्र सरकार को भेज दिया गया है और सतर्कता एवं भ्रष्टाचार-विरोधी विभाग को जांच करने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। विजिलेंस और एंटी करप्शन विभाग को उक्त साक्ष्यों के आधार पर केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने कहा कि ईडी ने पर्याप्त सबूत पेश कर दिए हैं, इसलिए प्रारंभिक जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी पत्रों में पर्याप्त सबूत होने का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने मामले दर्ज करने, जांच करने और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

''कलैगनार मगलीर उरिमाई थिट्टम'' योजना बाधित करने का प्रयास नाकाम हुआ : मंत्री

चेन्नई। तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेन्नारासु ने शुक्रवार को कहा कि कुछ तत्व कलैगनार मगलीर उरिमाई थिट्टम'' योजना को बाधित करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन वे नाकाम रहे। राज्य सरकार ने अपनी इस योजना के तहत प्रत्येक महिला लाभार्थी के बैंक खाते में 5,000 रुपये अंतरित किए हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही इस योजना को बाधित करने की कोशिश नाकाम हो गयी। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने 13 फरवरी को 1.31 करोड़ महिला लाभार्थियों के खातों में पांच-पांच हजार रुपये जमा कराने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इस राशि में एक-एक हजार रुपये की तीन मासिक किस्तें और परिवार की महिला मुखिया के लिए ग्रीष्मकालीन विशेष पैकेज के रूप में 2,000 रुपये शामिल हैं।

गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय
भारत सरकार
Serious Fraud Investigation Office
Government of India

SFIO

B-3 Wing, 2nd Floor
Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan
CGO Complex, Lodi Road
New Delhi-110003

बी-3 विंग, द्वितीय तल
पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन
केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोदी रोड
नई दिल्ली-110003

सं./क्रमांक : SFIO/DMN-II/BILLS/0034/2015-DMN-II-Part(1)(6528)/I/

इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से इस कार्यालय में निम्नलिखित रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के आधार पर भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं: -

क्रम संख्या	पदनाम	रिक्तियों की संभावित संख्या	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में स्तर	तैनाती का संभावित स्थान
	संयुक्त निदेशक (पूंजी बाजार)	01	स्तर-12	चेन्नई / दिल्ली / हैदराबाद / कोलकाता / मुंबई
	उप निदेशक (कॉरपोरेट कानून)	12	स्तर-11	
	उप निदेशक (जांच)	04		
	प्रधान निजी सचिव	01		
	वरिष्ठ सहायक निदेशक (बैंकिंग)	01	स्तर-10	
	वरिष्ठ सहायक निदेशक (पूंजी बाजार)	01		
	वरिष्ठ सहायक निदेशक (सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क)	01		
	वरिष्ठ सहायक निदेशक (फॉरेंसिक ऑडिट)	01		
	वरिष्ठ सहायक निदेशक (जांच)	07		
	वरिष्ठ सहायक निदेशक (कराधान)	01		
	वरिष्ठ अभियोजक	03		
	सहायक निदेशक (जांच)	12	स्तर-8	
	कुल रिक्तियां	45		

2. ये पद प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) के आधार पर भरे जाएंगे, निजी उम्मीदवारों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
3. विज्ञापित पदों की संख्या संभावित है और प्रशासनिक कारणों से इसमें वृद्धि या कमी हो सकती है। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार अपने आवेदन निर्धारित प्रारूप में, सभी प्रकार से पूर्ण कर, उचित माध्यम से निम्न पते पर भेज सकते हैं -

निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003. आवेदन इस विज्ञापन के रोजगार समाचार में प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए www.sfio.nic.in / www.mca.gov.in देखें।

4. प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन निर्धारित प्रारूप में भेजा जा सकता है। आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यताओं की स्वप्रमाणित प्रतियां, पिछले 5 वर्षों की अद्यतन एसीआर/एपीएआर (प्रत्येक पृष्ठ पर अवर सचिव या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित), सतर्कता स्वीकृति प्रमाणपत्र, सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र तथा पिछले 10 वर्षों में लगाए गए किसी भी प्रमुख/लघु दंड का प्रमाणपत्र संलग्न होना चाहिए।

कैडर नियंत्रण प्राधिकरण यह भी प्रमाणित कर सकता है कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरणों का सत्यापन कर उन्हें सही पाया गया है।

5. चयनित उम्मीदवारों को मूल वेतन का 20 प्रतिशत विशेष सुरक्षा भत्ता भी देय होगा। एसएसए के साथ कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।

6. जिन आवेदनों के साथ एसीआर/एपीएआर, सतर्कता स्वीकृति, शैक्षणिक योग्यता की स्वप्रमाणित प्रतियां आदि संलग्न नहीं होंगी अथवा जो आवेदन अपूर्ण पाए जाएंगे, उन्हें विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जाएगा।

वरिष्ठ सहायक निदेशक (प्रशासन)

CBC 07102/11/0017/2526

भारत सरकार
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
त्वरित कॉर्पोरेट समापन प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस),
आई.आई.सी.ए. बिल्डिंग, 7वीं मंज़िल,
प्लाट झ-6,7,8, से.-5, आई.एम.टी. मानेसर,
गुड़गाँव, हरियाणा - 122050.
ईमेल: roc.cpace@mca.gov.in

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Corporate Affairs
Centre for Processing Accelerated Corporate Exit (C-PACE)
IICA Building, 7th Floor,
Plot P-6,7,8, Sector-5, IMT Manesar,
Gurgaon, Haryana - 122050.
Email: roc.cpace@mca.gov.in

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

कंपनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में

सार्वजनिक नोटिस : ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2025-26/1991 दिनांक : 14/02/2026

संदर्भः

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (35) कंपनियों के नाम राज्य तमिलनाडु (आरओसी-चेन्नई)से हटाने के मामले में:

S No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AC1198414	U72900TN2020PTC135638	सॉफ्टेपिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
2	AC1619281	U72900TN2022PTC153454	विट्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड
3	AC1823064	U67190TN2013PTC091006	अन्नामनेनी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
4	AC2010458	U72900TN2018FTC122124	जियोडेक्सिया टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
5	AC2150456	U24290TN2016PTC113674	एवी एडिबल इंग्रेडिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड
6	AC2166801	U74999TN2016PTC104586	जिवेली फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
7	AC2238447	U29200TN2021PTC142498	ग्रेडियंट अंबत्तूर सीईटीपी प्राइवेट लिमिटेड
8	AC2247689	U74999TN2017PTC118782	सिगारम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
9	AC2091595	U72300TN1997PTC038982	कार्मेल सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड
10	AC1147504	U74999TN2021FTC146276	टीसीएफ ग्लोबल प्लेसमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
11	AC1606657	U74999TN2018PTC122709	एलवीजी वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड
12	AC1579699	U35105TN2023PTC161486	सुप्रीम सोलर पावर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
13	AC1623202	U78300TN2024PTC171909	एडीके ग्लोबल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
14	AC1162657	U46529TN2023PTC163088	गुड विंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
15	AC1647250	U63040TN2022PTC150994	वेलडन ट्रिप एंड इवेंट प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड
16	AC1706142	U72900TN2015PTC098999	ईप्रोडकास्ट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
17	AC1280054	U29309TN2022FTC151257	फाइबरलाइन कंपोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड
18	AC1720858	U29309TN1997PTC039585	कॉनमैक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
19	AC1753307	U40102TN2008PTC069461	जी.एम. एनर्जी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
20	AC1818794	U82990TN2025PTC183392	गिगा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
21	AC1883598	U31904TN2017PTC115663	सिंकप्रो टेक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
22	AC1922132	U74999TN2017PTC115100	एप्टटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
23	AC2015505	U63040TN2019PTC133181	लॉजिटिम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
24	AC2147018	U74900TN2015PTC100007	हार्वे इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
25	AC2130622	U47912TN2024PTC172636	खुलशाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
26	AC2136286	U72900TN2016PTC110619	बिनवेव टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
27	AC2142462	U15410TN2022PTC151989	रिविगोरेंट हेल्थ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
28	AC2130015	U82300TN2024PTC173474	बीवाईएम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
29	AC2167682	U29100TN2021PTC142396	ग्रेडिएंट कडेचूर सीईटीपी प्राइवेट लिमिटेड
30	AC1097817	U46305TN2024PTC175052	लुसेरा एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड
31	AC2156709	U78100TN2025OPC177887	एडवोस वर्ल्डवाइड एजु (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
32	AC2157771	U52599TN1997PTC037278	श्रीराम मार्केटिंग एजेंसिज (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड
33	AC2168860	U50400TN2018PTC125760	थामीरा मोटर स्पेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
34	AC2183966	U29304TN2023PTC162079	कपिलाभ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
35	AC1125789	U74999TN2016PTC111455	श्री साई स्नेहा टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कंपनियों के नाम कंपनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कंपनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कंपनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कंपनी ने निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कंपनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कंपनी रजिस्ट्रार से अपना / अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कंपनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कंपनियों के नामों को कंपनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कंपनी को कंपनी रजिस्ट्रार से कंपनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

रौनक अग्रवाल
उप-पंजीयक
त्वरित कॉर्पोरेट समापन प्रसंस्करण केंद्र

CBC 07123/11/00723/2526

शिक्षा मंत्री का कांग्रेस पर तीखा प्रहार पिछली सरकार ने बच्चों का भविष्य अंधकार में डाला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के मौजूदा सत्र में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को लेकर कांग्रेस को घेरा, वहीं कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने प्रदेश में खाद–बीज की स्थिति और मिलावटखोरों पर हुई कार्रवाई का ब्योरा पेश किया।

कांग्रेस ने बच्चों के साथ किया अत्याचारप्रदेश के स्कूलों में खाली पदों से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पिछली गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।

दिलावर ने कहा कि पिछली सरकार ने 6,264 स्कूलों को क्रमोन्नत तो कर दिया, लेकिन एक भी नया पद सृजित नहीं किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने बच्चों को क्लास में तो बैठा दिया, लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं था। लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया गया। मंत्री ने सदन को बताया कि वर्तमान सरकार 72 हजार रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पर काम कर रही है। 2024 और 2025 की भर्तियों के आंकड़े पेश करते हुए उन्होंने कहा कि हम युवाओं को रोजगार और बच्चों को शिक्षक देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 27 नकली खाद फैक्ट्रियों पर जड़े तालेखाद–बीज की किल्लत और मिलावटखोरी पर बोलते हुए कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार का पक्ष मजबूती से रखा।

डॉ. किरोड़ी ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में यूरिया और डीएपी की कोई कमी नहीं है। इस बार मानसून लंबा खिंचने के कारण रकबा बढ़ा और मांग बढ़ी, जिसे केंद्र के सहयोग से पूरा किया गया। मंत्री ने बताया कि नकली खाद–बीज बनाने वाली 27 फैक्ट्रियों को सीज कर उन पर ताले लटका दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले राज में रिटेलर ट्रेडर्स की आदतें बिगड़ गई थीं, जिन्हें अब सुधारा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि खाद की लाइनों में कहीं भी लाठीचार्ज या अनहोनी नहीं हुई, जैसा पिछली सरकार के समय आम बात थी।

मदन दिलावर के जवाब के दौरान बीच में टोकने पर विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) ने विधायक को कड़ी फटकार लगाई और संसदीय मर्यादा का पालन करने के निर्देश दिए। शनिवार को भी विधानसभा चलेगी। सरकार के दो साल के कामकाज पर 'दो साल बनाम पांच साल' की बहस होगी, जिसके बाद कल शाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सदन में जवाब देंगे।

घुमंतु, अर्ध घुमंतु समुदाय के लाभार्थियों को मिली पहचान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में 12 जनवरी से 15 फरवरी तक संचालित शिविरों में घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु (डीएनटी) समुदाय के 12 हजार 455 व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी किए गए। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उनके उत्थान और उन्हें समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए लगभग एक महीने के शिविर सभी जिलों में संचालित किए गए। शिविरों में कुल 17 हजार 21 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका परीक्षण कर 12 हजार 455 व्यक्तियों को शिविरों में पहचान पत्र जारी कर दिए गए। शेष का परीक्षण किया जा रहा है और प्रक्रियाधीन है।

गहलोत ने बताया कि प्रदेश में सर्वाधिक गंगानगर जिले में 1884, पाली में 1286, बीकानेर में 1263, अजमेर में 1006, अलवर में 969 समुदाय के लोगों को पहचान पत्र जारी किए गए। उन्होंने बताया कि शिविरों में ई–मित्र के माध्यम से निःशुल्क आवेदन की सुविधा प्रदान की गई थी। साथ ही अधिकारियों को मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र आदि बनवाकर मदद के लिए भी नियोजित किया गया था।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से समुदाय के अधिकाधिक व्यक्तियों को राज्य एवं केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का उद्देश्य सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया सतत जारी रखी जाएगी, ताकि समुदाय सरकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से उठा सके।

सरकारी मुख्य सचेतक गर्ग को स्पीकर का करारा जवाब, उप नेता प्रतिपक्ष को मैंने अनुमति दी है

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग की उस समय विचित्र स्थिति बन गई जब उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा के बार–बार उठने पर सवाल उठाया। उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि रामकेश मीणा उप नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं, इसलिए उन्हें नेता प्रतिपक्ष का प्रोटोकॉल नहीं मिल सकता। ऐसा किया जाना गलत है। गर्ग ने उदाहरण भी दिया कि पूर्व में जब गुलाबचंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष और राजेंद्र राठौड़ उप नेता प्रतिपक्ष थे। तब गुलाब जी की अनुपस्थिति में राठौड़ को सवाल पूछने की इजाजत नहीं दी जाती थी। इस पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग की आपत्ति को खारिज करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा कि मैंने उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा को अनुमति दी है। इसलिए वे प्रश्नकाल में किसी भी सवाल पर खड़े होकर मंत्री से जवाब मांग सकते हैं। सदन में यह दृश्य उस समय नजर आया जब प्रश्नकाल के दौरान सीवरेज ट्रींटमेंट प्लांट के पीपीपी मॉडल पर संचालन को लेकर विधायक गोपीचंद मीणा के मूल प्रश्न पर स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा जवाब दे रहे थे। इसी सवाल पर हस्तक्षेप करते हुए उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने स्वायत्त शासन राज्यमंत्री से कुछ स्पष्टीकरण चाहा था।

सनातन संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इसे मिटा सके : राज्यपाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सनातन मंगल महोत्सव को एतिहासिक आयोजन बताते हुए कहा कि सनातन संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन और समावेशी सोच रखने वाली है। इस तरह के आयोजन सनातन संस्कृति को मजबूत बनाने वाले है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो सनातन संस्कृति के प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति को मिटा सके। इसी श्रद्धा के कारण ये संस्कृति सुरक्षित है । महाभारत और रामायण जैसे ग्रन्थ इसी सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं।

राज्यपाल बागड़े ने शुक्रवार को हरिशेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा के तत्वावधान में आठ दिवसीय सनातन मंगल महोत्सव एवं दीक्षा दान समारोह में शिरकत की। उन्होंने वहाँ श्रीमद भागवत महापुराण कथा श्रवण कर श्रद्धालुओं को संबोधित किया। राज्यपाल ने कहा कि आठवीं सदी से ही सनातन संस्कृति को नष्ट करने के कई प्रयास होते रहे लेकिन आक्रमणकारी कभी सफल नहीं हो पाए।

हमारे साधु संतों के सनातन संस्कृति ओर धर्म को बचाने का कार्य करने से ये सदा सुरक्षित रही। राज्यपाल ने व्यास पीठ पर विराजित श्रीधाम वृन्दावन के कथा व्यास डॉ. श्यामसुन्दर पाराशर का अभिनंदन करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

राज्यपाल ने सनातन मंगल महोत्सव के तहत हो रहे विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का अवलोकन किया। उन्होंने विश्व शांति, सर्व संकट निवारण एवं विश्व कल्याण की भावना से प्रतिदिन हो रहे वैदिक अग्नि अनुष्ठान पंचकुण्डीय विष्णु महायज्ञ, अष्टोतर शत (108) भागवत मूल पाठ एवं शतचण्डी, अनवरत अखण्ड श्रीमद भगवतगीता पाठ, रामचरितमानस पाठ, श्रीचंद सिद्धांत सागर पाठ, अखण्ड रामनाम संकीर्तन स्थल का अवलोकन किया। उन्होंने इस भव्य आयोजन की सफलता के लिए मंगल कामना की।

मुख्य सचिव श्रीनिवास ने किया स्वास्थ्य भवन का निरीक्षण, साफ-सफाई व प्रबंधन में सुधार को सराहा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शुक्रवार प्रातः स्वास्थ्य भवन पहुंचकर मुख्य भवन एवं एनएचएम भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण करने के साथ ही कार्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और विगत दिनों में स्वास्थ्य भवन में हुए सुधारों की सराहना की। मुख्य सचिव प्रातः 9.30 बजे स्वास्थ्य भवन पहुंचे। उन्होंने मुख्य भवन एवं एनएचएम भवन का निरीक्षण करते हुए कार्मिकों की बैठक व्यवस्था, कार्यालयों में साफ–सफाई एवं कार्यालय प्रबंधन व्यवस्थाओं का विस्तार से अवलोकन किया। उन्होंने भवन में स्वच्छता, अनुपयोगी सामान के निस्तारण, कामकाज एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर विगत निरीक्षण में दिए गए निर्देशों की पालना पर सराहना व्यक्त की। साथ ही उन्होंने इसे निरंतर बनाए रखने और साफ–सफाई, रंग–रोगन आदि को लेकर आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। इस दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ भी साथ रहीं और कार्यप्रणाली आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की।

मुख्य सचिव ने पहले प्रथम तल पर निदेशक जन–स्वास्थ्य विंग एवं एनएचएम विंग का निरीक्षण किया। इसके बाद दूसरे तल पर परियोजना निदेशक एनएचएम कार्यालय, एनएचएम एचआर विंग में जाकर अवलोकन किया। तृतीय विंग पर राजहेल्थ पोर्टल अनुभाग एवं विधि विंग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पोर्टल के माध्यम से संचालित मानव संसाधन सूचना प्रणाली तथा अन्य डिजिटल मॉड्यूल्स की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने राज हैल्थ पोर्टल के माध्यम से राज्य के समस्त स्वास्थ्य कार्मिकों एवं अधिकारियों के ई–सर्विस रिकॉर्ड, ऑनलाइन अवकाश प्रबंधन, पदस्थापन स्थिति संधारण तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण कार्यप्रणाली का भी अवलोकन किया और पारदर्शिता के लिए किए जा रहे इन नवाचारों को सराहा।

वी. श्रीनिवास ने राज हेल्थ पोर्टल की उपयोगिता एवं पारदर्शिता की सराहना करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने निर्देश दिए कि डिजिटल प्रणाली के माध्यम से कार्यों के निष्पादन में और अधिक दक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटल नवाचारों को प्रोत्साहित किए जाने पर बल दिया ताकि राज्य के स्वास्थ्य तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

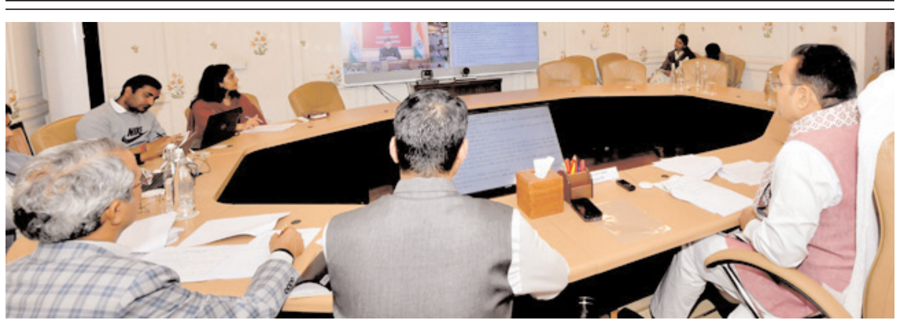

अधिकारी जनता की समस्याओं के समाधान को दें सर्वोच्च प्राथमिकता : भजनलाल शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार जन सेवा को सर्वोपरि मानकर कार्य कर रही है। अधिकारी जनता की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कार्मिक निष्ठा से अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन करें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज–उन्नति की बैठक को वीसी के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों की 84 हजार 282 करोड़ रुपये की परियोजनाओं और योजनाओं पर चर्चा की तथा अधिकारियों को इनके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि अधिकारी तय समय में विकास कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, जिससे परियोजनाओं की लागत में वृद्धि ना हो तथा जनता को राहत मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी सम्पर्क हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करें। साथ ही, जिला एवं विभाग स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारी इसकी नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कलक्टर्स को निर्देश दिए कि सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त समस्याओं के समाधान में देरी ना हो। साथ ही, नियमित जन सुनवाई करें, जिससे स्थानीय स्तर पर ही आमजन की परिवेदनाओं का निस्तारण सुनिश्चित हो सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान सम्पर्क हेल्पलाइन के चयनित परिवादियों से उनके परिवाद निस्तारण पर फीडबैक लिया। जैसलमेर के धन्नाराम सहित अन्य परिवादियों ने मुख्यमंत्री का समस्याओं के समाधान के लिए आभार जताया।

शर्मा ने पावर ग्रिड के प्रोजेक्ट्स को गुणवत्ता के साथ समय–सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने 765 केवी डी/सी ब्यावर–दौसा ट्रांसमिशन लाइन से संबंधित कार्य में गति लाने और 765 केवी डी/सी सीकर–खेतड़ी ट्रांसमिशन लाइन को भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। शर्मा ने उद्योग विभाग को भीलवाड़ा में बन रहे टेक्सटाइल पार्क में समस्त कार्य शीघ्र पूर्ण करते हुए भूखण्ड आवंटन प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र में आरएफआईडी एवं जीपीएस आधारित निगरानी प्रणाली को चरणबद्ध रूप से लागू करने के लिए मुख्य सचिव पाक्षिक रूप से बैठक करें। साथ ही, वेब्रिज ऑटोमेशन एवं वाहन टेक्रकिंग सिस्टम से संबंधित मॉडयूल को शीघ्र पूर्ण किया जाए। वहीं, खान विभाग एवं परिवहन विभाग आपसी समन्वय से पोर्टल का शीघ्र इंटीग्रेशन करें, जिससे खनिज परिवहन की वास्तविक समय निगरानी एवं ओवरलोडिंग नियंत्रण किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कौशल विकास कार्यक्रम के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की जिला कौशल समितियों को और अधिक सक्रिय करने के भी निर्देश दिए। साथ ही, न्यू एज कोर्स का कनवर्जेन्स करने तथा जिलों में स्किल गैप कवर करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष में 1 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कालीबाई भील उड़ान योजना के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को निःशुल्क सेनेटरी नेपकिन वितरण के लिए वितरण केन्द्रों पर सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा 5 साल में 6 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। अब तक 2 लाख से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से भी युवाओं के लिए रोजगार के भरपूर अवसर सृजित हुए हैं।

मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों का सदन से बहिर्गमन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के एक जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से बहिर्गमन किया। कांग्रेस विधायक राज्य में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के काम पूरे होने में देरी से जुड़े सवाल पर मंत्री के जवाब से असंतुष्ट थे। सदन में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए खर्रा ने पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की परियोजनाओं के काम में कमियों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में कई सीवरेज ट्रीटमेंट संयंत्र शुरू किए गए थे लेकिन उनके परिचालन एवं प्रबंधन में खामियां रहीं।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में बिछाई गई सीवरेज पाइपलाइन में 'अलाइनमेंट' संबंधी कमियां थीं। हमने संबंधित अधिकारियों के ज़रिए इन गलतियों को ठीक करने करवाने के प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए सरकार द्वारा दिए गए पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। कांग्रेस के विधायकों ने खर्रा के उत्तर पर एतराज जताते हुए हंगामा किया।

इस बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अगला प्रश्न पुकार लिया। कांग्रेस के विधायक यह कहते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये कि वह मंत्री के जवाब से खुश नहीं हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बहिर्गमन की निंदा की और कहा कि अनुकूल जवाब नहीं आने पर कांग्रेस के विधायकों ने बहिर्गमन किया है।

जोधपुर का भीतरी शहर फिर बॉलीवुड की पसंद

नवचौकिया में श्रुति हासन की फिल्म की शूटिंग शुरू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जोधपुर। नीली नगरी के नाम से मशहूर जोधपुर का भीतरी शहर एक बार फिर बॉलीवुड के कैमरों से गुलजार है। अपनी ऐतिहासिक गलियों और अनूठे स्थापत्य के लिए मशहूर इस इलाके में एक नई फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है, जिसे देखने के लिए स्थानीय लोगों में भारी उत्साह है।

कोतवाली स्कूल में सजे कैमरे फिल्म की शूटिंग फिलहाल शहर के नवचौकिया स्थित कोतवाली स्कूल में चल रही है। स्कूल परिसर को फिल्म के दृश्यों के अनुरूप तैयार किया गया है। भीतरी शहर की तंग गलियाँ और पुराने मकानों का बैकड्रॉप बॉलीवुड निर्देशकों को हमेशा से अपनी ओर आकर्षित करता रहा है, और यही कारण है कि एक बार फिर इस लोकेशन को चुना गया है।

इस विशेष शूट के लिए दक्षिण भारतीय फिल्मों और बॉलीवुड की जानी–मानी अभिनेत्री श्रुति हासन जोधपुर पहुँची हैं। श्रुति को देखने और शूटिंग की एक झलक पाने के लिए नवचौकिया इलाके में प्रशंसकों की भीड़ उमड़ रही है। सुरक्षा के लिहाज से शूटिंग स्थल पर कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि शूटिंग में किसी तरह का व्यवधान न आए। जोधपुर का भीतरी शहर 'भीतरी' संस्कृति और हेरिटेज लुक के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हाल के वर्षों में कई बड़े बैनर की फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग यहाँ हुई है। इस नई फिल्म की शूटिंग से स्थानीय पर्यटन और कला को एक बार फिर वैश्विक पहचान मिलने की उम्मीद है।

वर्तमान समय में बौद्धिक क्षमता व गुणवत्ता युक्त शिक्षा की अहम भूमिका : बागड़े

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि वर्तमान समय में बौद्धिक क्षमता व गुणवत्ता युक्त शिक्षा की अहम भूमिका है। यह मानवीय व्यवहार व आचरण को बेहतर बनाने में अमूल्य साबित होगी। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के केंद्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्रों में उत्कृष्टता के मानक स्थापित करें।

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शुक्रवार को भीलवाड़ा स्थित संगम विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल बागड़े ने कहा कि ज्ञान, कौशल एवं चरित्रकृये तीनों तत्व किसी भी राष्ट्र की प्रगति के आधार स्तंभ हैं। युवा शक्ति को इन मूल्यों के साथ आगे बढ़ते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन मूल्यों पर चलने का संदेश दिया।

राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में देश ने आत्मनिर्भर बनने के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, वर्तमान में बड़े सैन्य उपकरण, भारी मशीनरी इत्यादि का निर्माण देश में ही हो रहा है। राज्यपाल ने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह शैक्षणिक उपलब्धि का महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो विद्यार्थियों को जीवन के नए अध्याय में प्रवेश का अवसर प्रदान करता है। समारोह में शैक्षणिक सत्र 2024–25 के 30 स्नातक, स्नातकोत्तर व डिप्लोमा के विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक एवं 31 शोधार्थियों को उपाधियाँ प्रदान की गई।

आरटीई में बकाया राशि का भुगतान करे राज्य सरकार : गहलोत

जयपुर/दक्षिण भारत । पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार से शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों को बकाया राशि का भुगतान तुरंत करने के लिये कहा है कि ताकि गरीब तबके के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। गहलोत ने एक बयान में कहा, हमारी कांग्रेस सरकार ने राज्य के गरीब बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आरटीई का दायरा बढ़ाकर कक्षा 9 से 12 तक मुफ्त शिक्षा का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। इसके ठीक विपरीत, वर्तमान भाजपा सरकार से कक्षा एक से 8 तक की आरटीई फीस का 900 करोड़ रुपये का बकाया तक नहीं चुकाया जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया, निजी स्कूलों द्वारा नए प्रवेश रोकने की चेतावनी और पिछले साल के 44 हजार बच्चों का अब तक प्रवेश न होना मुख्यमंत्री जी के दो साल बनाम पांच साल के सुशासन के दावों की असलियत उजागर करता है। गहलोत के अनुसार, जो सरकार गरीब बच्चों की फीस का पुनर्भरण नहीं कर सकती, उसके बड़े–बड़े दावे केवल खोखले हैं।

राजनीति का शुद्धिकरण कर रहे मुख्यमंत्री आदित्यनाथः डॉ. डेविड फ्रॉले

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

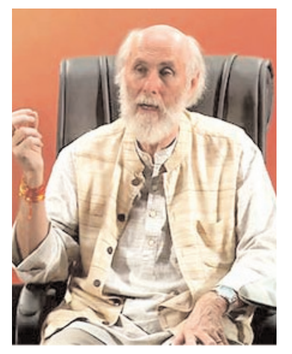

लखनऊ/भाषा। अमेरिका के वैदिक विद्वान डॉ. डेविड फ्रॉले ने राजधानी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और योग, आयुर्वेद एवं सनातन संस्कृति पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि योगी राजनीति का शुद्धिकरण कर रहे हैं। एक बयान में इसकी जानकारी दी गई है।

बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री के बहुआयामी व्यक्तित्व के प्रशंसक डॉ. फ्रॉले ने कहा कि 'योगी आदित्यनाथ राजनीति का शुद्धिकरण कर रहे हैं।' उन्होंने नाथ परंपरा का उदाहरण देते हुए कहा कि इससे वैश्विक कल्याण की नई राह प्रशस्त हो रही है। अमेरिकी विद्वान ने सरकार द्वारा अयोध्या का पुरातन गौरव लौटाने की सराहना की और कहा कि अयोध्या का कायाकल्प वेदों की ओर लौटने का मार्ग है।

बयान के मुताबिक फ्रॉले ने कहा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ समय बिताना मेरे लिए अत्यंत सम्मान और सौभाग्य की बात रही। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी उस नाथ परंपरा से जुड़े हैं, जो प्राचीन योग संस्कृति से जुड़ी है और इसे भारत में जीवंत बनाए हुए है।'' इसमें कहा गया है, ''वह इन परंपराओं को न केवल संरक्षित कर रहे हैं, बल्कि उन्हें वैश्विक स्तर पर विस्तार भी दे रहे हैं। साथ ही वे शरीर, मन, समाज के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि आदित्यनाथ राजनीति का शुद्धिकरण भी कर रहे हैं। भारत की वे सभी परंपराएं, जो संपूर्ण मानवता के लिए प्रासंगिक हैं, योगी के माध्यम से नई ऊर्जा प्राप्त कर रही हैं।

फ्रॉले ने 'नई अयोध्या' की प्रशंसा करते हुए कहा कि अयोध्या का कायाकल्प अत्यंत प्रसन्नता की बात है।

विसकॉन्सिन (अमेरिका) में एक कैथोलिक परिवार में जन्मे डॉ. डेविड फ्रॉले की गिनती अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदुत्व के प्रमुख विचारकों में होती है।

नौ वर्षों में स्पष्ट नीति, शुद्ध नीयत, प्रभावी वित्तीय प्रबंधन से परिवर्तन : योगी आदित्यनाथ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विधानसभा में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि राज्य में पिछले नौ वर्षों में आया परिवर्तन स्पष्ट नीति, शुद्ध नीयत और प्रभावी वित्तीय प्रबंधन का परिणाम है।

मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट पर विधानसभा में हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने नीचे के तीन राज्यों की श्रेणी से निकलकर देश के शीर्ष तीन राज्यों में स्थान बनाया है।

उन्होंने राजकोषीय अनुशासन पर विपक्ष को आईना दिखाते हुए कहा कि वर्ष 2016-17 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 4.39 प्रतिशत था, जो 2025-26 में घटकर 2.97 प्रतिशत रह गया है।

इसी तरह ऋणग्रस्तता भी लगभग 30 प्रतिशत से घटकर 26 प्रतिशत के आसपास आ गई है और 2026-27 तक इसे 23 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है।

उन्होंने बताया कि 2016-17 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय लगभग 43,000 रुपए थी, जो 2024-25 के अंत तक

1,20,000 रुपए से अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन उत्तर प्रदेश की आर्थिक मजबूती और विकास की गति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 2016-17 में उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों में निचले पायदान पर था, लेकिन आज प्रदेश ने अपनी जीएसडीपी को 13 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 36 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाया है और 2026-27 में इसे 40 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता दी गई है। वर्ष 2016-17 में यह लगभग 71,000 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर एक लाख 77 हजार करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुनियादी ढांचे में निवेश से रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलती है। बुनियादी ढांचे पर किया गया निवेश केवल ढांचा निर्माण नहीं करता, बल्कि रोजगार सृजन, उद्योगों के विस्तार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में एक रुपए का निवेश पांच से छह गुना प्रतिफल देता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को एक लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य इसी बजट के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और यह बजट उसी दिशा में एक ठोस कदम है।

अमित शाह ने असम के कछार में भारत-बांग्लादेश सीमा का निरीक्षण किया

नाथनपुर (असम)/भाषा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को असम के कछार जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा का निरीक्षण किया। नाथनपुर सीमावर्ती गांव के अपने दौरे के दौरान शाह के साथ मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य सरकारी अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों ने बताया कि शाह ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। गृह मंत्री ने यहां बीएसएफ के शिविर में शहीदों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और प्रदर्शित किए गए हथियारों का निरीक्षण किया। उन्होंने सीमा के पास बरगद का पेड़ भी लगाया। असम बांग्लादेश के साथ 267.5 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिसमें भूमि और नदी सीमा दोनों शामिल हैं। यह सीमा धुबरी, दक्षिण सालमारा-मनकाचर, कछार और करीमगंज जिलों के कुछ हिस्सों को कवर करती है। कछार में सीमा का 27.3 कि.मी. हिस्सा पड़ता है।

ओडिशा सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश किया 3.1 लाख करोड़ रुपए का बजट

भुवनेश्वर/भाषा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 3.10 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में कृषि, ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। कुल बजट का लगभग 58 प्रतिशत (1,80,000 करोड़ रुपए) कार्यक्रम व्यय के लिए आरक्षित किया गया है। माझी ने राज्य विधानसभा में अपनी सरकार का तीसरा बजट पेश करते हुए कहा कि प्रशासनिक व्यय 1,14,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जबकि आपदा जोखिम प्रबंधन कोष के लिए 5,375 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में अनुमानित 72,100 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 6.5 प्रतिशत और राज्य बजट का 23.3 प्रतिशत है। उन्होंने 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना' योजना की घोषणा करते हुए कहा, महिला सशक्तिकरण के तहत हमारी सरकार का एक उद्देश्य यह है कि हर लड़की उच्च शिक्षा पूरी करे।

गुवाहाटी हवाई अड्डे का नया टर्मिनल 22 फरवरी से चालू होगा : हिमंत विश्व शर्मा

गुवाहाटी/भाषा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि गुवाहाटी हवाई अड्डे का 4,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नया टर्मिनल भवन 22 फरवरी से चालू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 20 दिसंबर को लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (एलजीबीआईए) के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया था। शर्मा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा, कुछ ही वर्षों में एक खुले स्थान से विश्व स्तरीय 'प्रवेश द्वार' तक का सफर। यह परिवर्तन अधिक 'कनेक्टेड' और आत्मविश्वास से भरे असम के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने कहा, ''आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने गुवाहाटी हवाई अड्डा का उद्घाटन किया था जिसका संचालन 22 फरवरी से शुरू किया जाएगा।'' एक अधिकारी ने बताया कि मार्च तक नए टर्मिनल से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों उड़ानें शुरू होने की संभावना है, जबकि पुराने टर्मिनल से मालवाहक विमानों का परिचालन किया जाएगा।

सहजीवन साथी ने 19 वर्षीय छात्रा को पीटा, गंभीर हालत में एम्स में भर्ती

गुरुग्राम/भाषा। हरियाणा के गुरुग्राम में 19 वर्षीय छात्रा को उसके सह-जीवन साथी ने कथित रूप से बेरहमी से पीटा जिसके बाद उसे गंभीर हालत में दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान दिल्ली निवासी शिवम (19) के रूप में हुई है। पीड़िता उत्तरी त्रिपुरा की रहने वाली है और गुरुग्राम के जीडी गोयनका विश्वविद्यालय में जैव प्रौद्योगिकी की छात्रा है।

पुलिस के अनुसार, दोनों की मुलाकात सितंबर 2025 में हुई थी और वे पिछले कुछ महीनों से सेक्टर 69 स्थित एक पीजी आवास में साथ रह रहे थे। उनके विवाह को लेकर परिवारों के बीच बातचीत चल रही थी। बृहस्पतिवार रात को दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी ने युवती पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बृहस्पतिवार देर रात युवती की मां की सूचना पर पुलिस पीजी पहुंची और युवती को निकाला।

हिमंत को 10 साल पुराने मुद्दे के बजाय अगले पांच वर्षों की योजनाओं पर बोलना चाहिए : प्रियंका गांधी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गुवाहाटी/भाषा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा ने शुक्रवार को कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को राज्य में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री बनने की उनकी कथित संभावना के बारे में ''10 साल पुराने'' मुद्दे को उठाने के बजाय रोजगार, विकास और अगले पांच वर्षों की योजनाओं पर बात करनी चाहिए।

प्रियंका ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कथित भ्रष्टाचार, ''एक परिवार'' में धन के केंद्रीकरण और राज्य की संपत्तियों को बड़े उद्योगपतियों को ''सौंपने'' को लेकर शर्मा पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि असम के लोग यह महसूस कर रहे हैं कि ''बदलाव'' का समय आ गया है। शर्मा के हाल के उन दावों के बारे में पूछे जाने पर जिनमें उन्होंने कांग्रेस की ओर से राज्य का मुख्यमंत्री बनने की संभावना जताई थी, प्रियंका ने कहा, ''राजनीति में कई फैसले लिए जाते हैं। कुछ पक्ष में जाते हैं, कुछ विपक्ष में। हमें इसे स्वीकार करना होगा। अगर वह (शर्मा) अभी भी 10 साल पुराने मुद्दे को उठा रहे हैं तो मैं क्या कहूं।'' शर्मा ने मंगलवार को दावा किया था कि 2014 में जब कांग्रेस के 58 विधायकों ने उनका समर्थन किया था, तब कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनसे पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने की तारीख तय करने को कहा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि हालांकि, उस समय अमेरिका यात्रा पर गए राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को फोन किया और स्थिति बदल गई। असम में 2011 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में असंतोष देखा गया था, जब विधायकों के एक वर्ग ने तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की जगह शर्मा को मुख्यमंत्री के तौर पर समर्थन दिया था। शर्मा 2015 में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए थे और उन्होंने 2016 के विधानसभा चुनावों में राज्य में भाजपा की पहली जीत सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई थी।

मप्र में दो समुदायों के बीच झड़प, पथराव और तोड़फोड़ की घटना हुई; पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े

जबलपुर/भाषा। मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले के सिहोरा कस्बे में बीती रात उस समय तनाव व्याप्त हो गया जब दो समुदायों के सदस्यों के बीच झड़प हुई, दोनों तरफ से पथराव किया गया और दुकानों तथा वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े।

अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना बृहस्पतिवार रात कस्बे के आजाद चौक इलाके में हुई, जिसके बाद वहां बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया। झड़प के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी आए हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आजाद चौक इलाके में दुर्गा देवी का मंदिर और मस्जिद हैं। आरती के दौरान, मंदिर की टूटी हुई सुरक्षा ग्रिल को लेकर दोनों समुदायों के सदस्यों बीच झड़प हो गई। उन्होंने बताया कि यह कहासुनी जल्दी ही हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि सड़क पर खड़े वाहनों और दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने शुरू में हल्का बल प्रयोग किया, लेकिन जब झड़प रुकने के कोई संकेत नहीं मिले, तो स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ प्रशासन के अधिकारियों ने भी स्थिति का जायजा लेने के लिए घटनास्थल का दौरा किया। जिला कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कहा कि स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है।

प्रधानमंत्री के 'समर्पण' के कारण भारत एक 'डेटा कॉलोनी' बन जाएगा : राहुल गांधी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उनके ''शर्मनाक समर्पण'' के कारण अब भारत एक 'डेटा कॉलोनी' बनकर रह जाएगा।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने एक वीडियो जारी कर सदन में बजट पर चर्चा के दौरान दिए गए अपने भाषण के उस अंश का जिक्र भी किया जिसमें उन्होंने मार्शल आर्ट की एक आधुनिक शैली 'जिउ-जित्सु' के 'ग्रिप' और 'चोक' जैसे कुछ दांव का उल्लेख किया था।

राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''व्यापार समझौते को लेकर संसद में अपने भाषण में मैंने 'जिउ-जित्सु' का उदाहरण क्यों दिया? अमेरिकियों को खुश करने के लिए हमारे किसानों की कुर्बानी क्यों दी गई? अमेरिका को हमारा तेल आयात तय करने की मंजूरी देकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता क्यों किया गया?'' उन्होंने सवाल किया कि बिना किसी पारस्परिक वादे के, हर साल 100 अरब डॉलर का अमेरिकी आयात बढ़ाने पर सहमति क्यों दी गई? उन्होंने दावा किया कि यह समझौता भारत को एक 'डेटा कॉलोनी' बना देगा क्योंकि सारा डेटा अमेरिका और उसकी कंपनियों के सुपुर्द किया जा रहा है।

राहुल गांधी ने कहा, ''मोदी जी ऐसा समझौता क्यों मानेंगे, जिसमें भारत इतना कुछ दे रहा है और बदले में बहुत कम मिलता दिख रहा है? इस शर्मनाक आत्मसमर्पण का जवाब प्रधानमंत्री पर डाले गए 'ग्रिप' और 'चोक' में छिपा है।''

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि प्रधानमंत्री के झुकने का कारण अमेरिका में उद्योगपति गौतम अदाणी के खिलाफ दर्ज मुकदमा और 'एप्सटीन फाइल' है। उन्होंने यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री की पैसे की बदौलत बनाई गई छवि की डोर अब अमेरिका के हाथों में है।

भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ पर रेखा गुप्ता बोलीं- सकारात्मक बदलाव के लिए सभी क्षेत्रों में काम किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार ने पिछले एक वर्ष में सभी क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने और गरीबों के कल्याण के उद्देश्य से काम किया है। पिछले साल हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की भारी जीत के बाद गुप्ता और उनकी मंत्रिपरिषद ने 20 फरवरी 2025 को शपथ ली।

दिल्ली सचिवालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भाजपा शासन के तहत पिछले एक वर्ष में किए गए कठिन परिश्रम और बदलावों का एक तथ्य पत्रक है और इसके लिए अंत्योदय के दर्शन का पालन किया गया है। उन्होंने कहा कि कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना को लागू करने का निर्णय लिया, जिसमें सात लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है और अब तक 30,000 से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। गुप्ता ने कहा, हमने दिल्ली की कार्य संस्कृति को बदल दिया है। पिछली सरकार बहुत शोर मचाती थी। हमने दिल्ली के सभी क्षेत्रों में काम किया है। आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा का निर्णय पहली कैबिनेट बैठक में ही ले लिया गया था। अब तक लगभग 30,000 लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार शहर में गरीबों और झुग्गीवासियों के कल्याण के लिए भी प्रतिबद्ध है, और इसके लिए उन्होंने शहर में जेजे क्लस्टर के विकास के लिए बजट में 700 करोड़ रुपए के आवंटन का हवाला दिया।

भारत-अमेरिका समझौते के खिलाफ 'किसान सम्मेलन' करेगी कांग्रेस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस ने शुक्रवार को फैसला किया कि अमेरिका के साथ हुए अंतरिम व्यापार समझौते के खिलाफ पार्टी अलग-अलग राज्यों में किसान सम्मेलन का आयोजन करेगी, जिनके माध्यम से किसानों को यह बताया जाएगा कि इस समझौते का उनकी आजीविका पर नकारात्मक असर पड़ने वाला है।

पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें यह फैसला किया गया। इस बैठक में इन राज्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक दल के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि पहला 'किसान सम्मेलन' 24 फरवरी को भोपाल में होगा तथा दूसरा 'किसान सम्मेलन' सात मार्च को महाराष्ट्र के यवतमाल में आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि तीसरा 'किसान सम्मेलन' मार्च महीने में राजस्थान के श्रीगंगानगर में होगा। रमेश ने बताया कि इन सम्मेलनों में खरगे और राहुल गांधी शामिल होंगे। उन्होंने कहा, ''बैठक में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किए गए 'सरेंडर' के बारे में चर्चा हुई। इस समझौते के कारण इन छह राज्यों के कपास, सोयाबीन, मक्का किसान और फल-मेवे के उत्पादकों पर नकारात्मक असर पड़ेगा।''

अर्जुन वृक्ष आधारित हर्बल उद्योग को बढ़ावा देने पर सरकार गंभीर : मंगल पांडेय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि अर्जुन (टर्मिनलिया अर्जुन) एक महत्वपूर्ण औषधीय वृक्ष है, जिसकी छाल का आयुर्वेदिक एवं आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में, विशेषकर हृदय रोगों के उपचार में व्यापक उपयोग होता है। पांडेय ने कहा कि उत्तर बिहार में इसकी उपलब्धता राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक एवं औषधीय संसाधन है।

मंत्री ने बताया कि बिहार राज्य औषधीय पादप बोर्ड राज्य में औषधीय पादपों के संरक्षण, संवर्धन, वैज्ञानिक कटाई (सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग), मूल्य संवर्धन तथा विपणन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आवश्यकता अनुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, कृषि विभाग तथा उद्योग विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर व्यवहारिक एवं विधिसम्मत कार्ययोजना तैयार की जाएगी, ताकि रोजगार सृजन के साथ-साथ राज्य में हर्बल मेडिसिन क्षेत्र को सुदृढ़ किया जा सके। मंत्री सदन में अलीनगर की विधायक मैथिली ठाकुर द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सरकार का पक्ष रख रहे थे। ठाकुर ने अपने प्रस्ताव में उत्तर बिहार में अर्जुन (टर्मिनलिया अर्जुन) वृक्ष की प्रचुरता का उल्लेख करते हुए इसे राज्य की बड़ी आर्थिक एवं आयुर्वेदिक संपत्ति बताया और इसके सुनियोजित दोहन एवं प्रसंस्करण के लिए सरकारी पहल की मांग की।

अनुभव तभी आता है जब आप द्विपक्षीय श्रृंखला में बड़ी टीम से खेलते हैं : राशिद खान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/भाषा। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने बृहस्पतिवार को यहां अपने आखिरी ग्रुप मैच में कनाडा को हराकर टी20 विश्व कप से शानदार तरीके से विदा लेने के बाद कहा कि क्रिकेट खेलने वाले मजबूत देशों के खिलाफ द्विपक्षीय श्रृंखलाएं होनी चाहिए क्योंकि इनसे अनुभव मिलता है। अफगानिस्तान ने टूर्नामेंट रोमांचक क्रिकेट खेला और एक मुकाबले में स्कोर बराबर होने के बाद दूसरे सुपर ओवर में दक्षिण अफ्रीका से हार गया।

हालांकि स्पिन गेंदबाजी के इस दिग्गज ने कहा कि अगर अफगानिस्तान को नियमित रूप से क्रिकेट खेलने वाले मजबूत देशों के खिलाफ मौके मिलते हैं तो वह काफी आगे बढ़ सकता है।

राशिद ने बृहस्पतिवार रात को कनाडा को 82 रन से हराने के बाद कहा, ''कुछ विभाग में सुधार की जरूरत है। बड़ी टीमों के खिलाफ मध्यक्रम बल्लेबाजी बिखर गई और डेथ ओवर में गेंदबाजी में भी सुधार चाहिए। पर यह सुधार तब होता है जब आप द्विपक्षीय सीरीज में बड़ी टीमों के साथ खेलते हैं।'' उन्होंने मैच में 19 रन देकर दो विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया। इस दिग्गज खिलाड़ी ने कहा कि टीम टूर्नामेंट के लिए अच्छी तैयारी के साथ आई थी और उसने जबरदस्त क्रिकेट खेला। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि दक्षिण अफ्रीका से मिली करीबी हार महंगी पड़ी।

राशिद खान ने कहा, ''हम (टूर्नामेंट के लिए) अच्छी तरह तैयार थे। हमने जबरदस्त क्रिकेट खेला। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच ने सच में सभी को दुखी किया। हमें उन (पहले दो) मैचों में से एक में जीत दर्ज करनी थी और देखना था कि टूर्नामेंट कैसा होता है। हम इस विश्व कप से सकारात्मक चीजें लेकर आगे बढ़ेंगे।''

मुख्य कोच जोनाथन ट्रॉट का कार्यकाल खत्म हो गया और राशिद ने इसे टीम के लिए भावुक पल बताया। उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि हमने उसके साथ कुछ बहुत अच्छे पल बिताए। हम अभी जहां हैं, वहां उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है। उनका जाना हमारे लिए भावनात्मक पल है। लेकिन जिंदगी ऐसी ही होती है। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।''

इब्राहिम जदरान को 56 गेंद में नाबाद 95 रन बनाने के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

सुविचार

अपने वह नहीं जो तस्वीर
में साथ हो अपने वह हैं जो
तकलीफ में साथ हो।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

मुफ्त की 'रेवड़ियां' नहीं, रोजगार दें

उच्चतम न्यायालय ने देश में चुनावों से पहले मुफ्त सुविधाएं देने के बढ़ते चलन की आलोचना कर इस मुद्दे पर सख्त टिप्पणी की है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं जुटा सकता, क्योंकि इससे वोटबैंक नाराज हो सकता है। यह जोखिम कौन मोल ले? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और चिकित्सा जैसी सुविधाएं सबको मुफ्त मिलनी चाहिएं। जो व्यक्ति बहुत ही जरूरतमंद है, शारीरिक या मानसिक स्थिति के कारण कामकाज करने में सक्षम नहीं है, उसे मुफ्त राशन जरूर मिलना चाहिए। वहीं, ऐसे लोग जो कई बीघा जमीनों के मालिक हैं, शानदार घरों में रहते हैं, सभी सुख-सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, जो अपने चौपहिया वाहनों में घूम रहे हैं, वे मुफ्त सुविधाएं पाने के हकदार कैसे हो सकते हैं? आज मुफ्त सुविधाओं की घोषणा करने के लिए राजनीतिक दलों में होड़ मची है। जो जितनी बड़ी घोषणाएं करता है, वह उतना ही जनहितैषी समझा जाता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उदय के बाद ऐसी घोषणाएं ज्यादा होने लगीं। इन्हें पूरी करने के लिए रुपए कहां से आ रहे हैं? क्या राजनीतिक दल अपने खाते से दे रहे हैं? करदाताओं से इकट्ठा किया गया धन यूं मुफ्तखोरी पर उड़ा देंगे तो देश का विकास कैसे होगा? उच्चतम न्यायालय के इन शब्दों पर हर राजनेता को चिंतन करना चाहिए- 'अगर आप सुबह से शाम तक मुफ्त भोजन देना शुरू कर देंगे, फिर मुफ्त साइकिल, मुफ्त बिजली देंगे, तो कौन काम करेगा और फिर कार्य संस्कृति का क्या होगा?' यह भी ध्यान रखें कि जब लोगों को मुफ्तखोरी का चस्का लग जाता है तो उससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। फिर वे ऐसी हर सुविधा को अपना अधिकार समझने लगते हैं। सरकारों को बहुत सोच-समझकर ही ऐसी सुविधाओं की घोषणा करनी चाहिए। उनका कर्तव्य है कि वे ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसरों का सृजन करें। ऐसे वातावरण का निर्माण करें, जिसमें उद्योग-धंधे पनपें। लोगों को हुनर सिखाएं। उन्हें इस लायक बनाएं कि वे खुद कमाएं और अपने लिए संसाधन जुटाएं।

सरकार को महंगाई पर नियंत्रण रखना चाहिए। रोटी महंगी न हो। कम कीमत पर बिजली, पानी जैसी सुविधाएं मिलें। दवाइयां हर परिवार की पहुंच में हों। आम आदमी सुखी रहे। वह सम्मानपूर्वक जीवन बिताए। लोगों को मुफ्त यात्रा कराने के बजाय ऐसी योजनाएं लाएं, जो उनके भविष्य को बेहतर बनाएं। उदाहरण के लिए- यात्रा टिकट सस्ता करें। उसके साथ यह योजना लागू करें कि जो यात्री हमेशा टिकट लेकर यात्रा करेगा, उसे बैंक एफडी और अन्य बचत योजनाओं में ज्यादा ब्याज मिलेगा। इसे बिजली और पानी के बिलों से भी जोड़ा जा सकता है। जो नागरिक समय पर बिल जमा कराए, उसे बचत योजनाओं में विशेष लाभ दिया जाए। इन्हें आधार कार्ड से जोड़ा जाए और एआई की मदद से डिजिटल निगरानी रखी जाए, ताकि धांधली की गुंजाइश न रहे। इस तरह लोगों को अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा मिलेगी। वे बचत योजनाओं से जुड़ेंगे तो सरकार के पास विकास के लिए ज्यादा धन होगा। सरकारें नकद सहायता भी दे रही हैं। क्या इससे गरीबी दूर हो जाएगी? इतिहास गवाह है, रुपए बांटने से न तो गरीबी दूर होती है, न लोगों की स्थिति सुधरती है। इससे कुछ समय के लिए राहत जरूर मिलती है। उसके बाद सबकुछ पुराने ढर्रे पर चलने लगता है। लोगों को रुपए बांटने की जगह कोई काम सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। जब व्यक्ति स्वरोजगार की राह पर चलने के लिए तैयार हो, तब उसे सहायता दी जाए, जिससे वह जरूरी सामान खरीद सके। उदाहरण के लिए- दो लोग हैं, जिन्हें दस-दस हजार रुपए की नकद सहायता दी जाएगी। पहले व्यक्ति के बैंक खाते में रुपए आने के बाद वह उनसे कुछ चीजें खरीदेगा। वह एक-दो महीने में पूरी राशि खर्च कर देगा। दूसरा व्यक्ति थोड़ा-सा सामान खरीदकर अपना काम शुरू करेगा। वह शुरुआती लाभ से उसे आगे बढ़ाएगा। वह भविष्य में गरीबी और बेरोजगारी के चक्र से बाहर निकल जाएगा। सरकारों को चाहिए कि वे लोगों को आत्मनिर्भर बनना सिखाएं। मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने से भविष्य में आर्थिक, सामाजिक और नैतिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं ।

ट्वीटर टॉक

आज मुख्यमंत्री कार्यालय मे आयोजित बैठक में भगवान ब्रह्मा जी की पावन नगरी पुष्कर के विकास के संबंध में कार्ययोजना की समीक्षा की और तीर्थराज पुष्कर को विश्वस्तरीय तीर्थाटन और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए।

-भजनलाल शर्मा

समस्त प्रदेशवासियों को विश्व सामाजिक न्याय दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए, इस अवसर पर जाति, धर्म, वंश, वर्ग के सारे भेदभाव भुलाकर एक-दूसरे के मानवीय अधिकारों का सम्मान करने का प्रण लें।

-दिया कुमारी

जब जुबीन गर्ग जी की मृत्यु हुई तो असम की हर आंख में आंसू थे। वे असम की जनता की आवाज थे। उन्होंने अपने गानों में हमेशा प्रेम, लगाव और एकता की बातें कीं। असम की जनता उनसे इतना लगाव इसलिए रखती है क्योंकि ये भावनाएं असम की जनता की भावनाएं हैं।

-प्रियंका गांधी वाड्रा

प्रेरक प्रसंग

स्वाभाविक राह

एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और बोला, 'गुरुदेव, मैं हमेशा दूसरों से तुलना करता हूं। कोई मुझसे तेज़ है, कोई मुझसे बुद्धिमान। मैं कब आगे बढ़ूंगा?' गुरु उसे जंगल में ले गए। वहां दो पेड़ थेएक लंबा, सीधा साल का पेड़ और उसके पास छोटासा आम का पौधा। शिष्य बोला, 'साल का पेड़ कितना महान है, और यह आम का पौधा कितना छोटा!' गुरु ने कहा, 'साल का पेड़ सौ साल में इतना बड़ा हुआ है, और यह आम का पौधा पांच साल में फल देने लगेगा। दोनों का मार्ग अलग है, पर दोनों प्रकृति के लिए आवश्यक हैं।'

फिर गुरु बोले, 'यदि आम का पौधा साल बनने की कोशिश करे, तो वह फल देना भूल जाएगा। और साल अगर आम बनने लगे, तो अपनी छाया खो देगा। महानता तुलना में नहीं, अपने स्वभाव को पहचानने में है।' शिष्य की आंखों में प्रकाश आ गया। उसने उसी दिन से दूसरों से नहीं, अपने कल से आगे बढ़ने का संकल्प लिया कि दूसरों की राह देखकर मत ठहरो, अपने स्वभाव की राह पर चलोवहीं तुम्हारी सच्ची महानता है।

सामयिक

राज्यसभा चुनाव में बढ़ेगी एनडीए की ताकत

राजेश माहेश्वरी

राज्यसभा में एक बड़ा बदलाव का इस साल होने वाला है। पूरे साल में करीब 72 से 75 सीटें खाली हो रही हैं, जो अप्रैल, जून, जुलाई और नवंबर में रिटायरमेंट से होंगी। अभी फरवरी 2026 में राज्यसभा की कुल 245 सीटों में बीजेपी की 103 हैं, कांग्रेस की 27, तृणमूल कांग्रेस की 12, आप की 10, डीएमके की 10, बीजेडी की 7, वाईएसआरसीपी की 5 और एआईएडीएमके की 7 सीटें हैं। नॉमिनेटेड 7 हैं और कुल एनडीए की ताकत 121 के आसपास है, जबकि इंडिया ब्लॉक के पास 80 सीटें हैं। लेकिन आने वाले चुनावों से यह आंकड़ा काफी हिलने वाला है।

राज्यसभा की इन 37 सीटों में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से सात सीटें खाली हो रही हैं, जिन पर चुनाव है। महाराष्ट्र की सात राज्यसभा सीटों में से बीजेपी के पास दो और शरद पवार की एनसीपी के पास 2 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और आरपीआई के पास एक-एक सीटें है। नंबर गेम्स के अनुसार सत्तारूढ़ एनडीए को 7 से 9 सीटों का फायदा होने की उम्मीद है, जिससे उनकी ताकत 145 तक पहुंच सकती है। वहीं, इंडिया ब्लॉक को 5 सीटों का नुकसान हो सकता है, जो उनकी संख्या को 75 के आसपास ला देगा। सबसे पहले आगामी 16 मार्च को 37 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जो 10 राज्यों से हैं। महाराष्ट्र से 7, ओडिशा से 4, तमिलनाडु से 6, पश्चिम बंगाल से 5, असम से 3, बिहार से 5, छत्तीसगढ़ से 2, हरियाणा से 2, हिमाचल प्रदेश से 1 और तेलंगाना से 2 सीट। ये सीटें अप्रैल में खाली हो रही हैं। साल के बाकी चुनावों में और 35-38 सीटें शामिल होंगी, जो कुल 22 राज्यों से हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से 10, कर्नाटक से 4, गुजरात से 4, आंध्र प्रदेश से 4 सीट।

राज्यसभा की वोटिंग के बाद 37 नए सांसद जुड़ेंगे। दस राज्यों की खाली सीटों में कांग्रेस के लिए हिमाचल एक बड़ा ठौर होगा। इस साल 72 सीटों पर चुनाव होंगे और इस तरह भाजपा का पलड़ा थोड़ा सा और भारी हो सकता है। हाल के विधानसभा चुनावों ने एनडीए की पोजीशन मजबूत की है। मसलन, महाराष्ट्र में एनडीए के 228 विधायक हैं (बीजेपी 131, शिवसेना-शिंदे 57, एनसीपी-अजित 40), जो 7 सीटों में से 4-5 जीत सकता है यानी पहले से ज्यादा। बिहार में एनडीए को एक एक्स्ट्रा सीट मिल सकती है, जहां पहले से 3 थे, अब 4। आंध्र प्रदेश में 3 गेन, गुजरात में 1, ओडिशा में 2, राजस्थान में 1। ये गेन विधानसभा स्ट्रेंथ से आते हैं, जैसे महाराष्ट्र में एनडीए ने 2025 चुनाव जीता, बिहार में एनडीए मजबूत, हरियाणा में बीजेपी, झारखंड में बीजेपी. हालांकि, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में 1-1 सीट का नुकसान हो सकता है।

राज्यसभा के सदस्य (सांसद) राज्य की विधानसभा के चुने हुए विधायकों की वोटिंग से चुने जाते हैं। यानी, केंद्र में कौन सी पार्टी मजबूत होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हर राज्य की विधानसभा में किस पार्टी के कितने विधायक हैं। अगर विधानसभा में आपकी पार्टी की ताकत बढ़ती है, तो राज्यसभा में भी आपकी सीटें बढ़ती हैं।

राज्यसभा की सीटें हर राज्य में तय होती हैं। जैसे महाराष्ट्र से 19 सीटें, लेकिन चुनाव साल दर साल कुछ सीटों पर होते हैं, जब पुराने सदस्य रिटायर होते हैं। चुनाव में जीतने के लिए, हर उम्मीदवार को एक निश्चित संख्या में वोट चाहिए, जिसे क्वोटा' कहते हैं। राज्यसभा के सदस्य विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स चुनते हैं, इसलिए हर राज्य में विधायकों की संख्या से कोटा तय होता है। यह इसलिए है कि हर सीट के लिए वोटस बराबर बंटें और कोई पार्टी ज्यादा वोटस से ज्यादा सीटें जीत सके। अगर किसी उम्मीदवार को कोटा से एक वोट भी कम मिला, तो वो हार जाता है।

कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक को सबसे ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि 5 से 6 सीटें कम हो सकती हैं। जैसे गुजरात में कांग्रेस की 1 सीट खत्म हो सकती है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल को लॉस, कर्नाटक में कांग्रेस को 1 कम। बीजेडी ओडिशा में 1-2 कम, वाईएसआरसीपी आंध्र में 3 कम, सीपीआई एम पश्चिम बंगाल से 1 कम। ये पार्टियां जहां विधानसभा में कमजोर हुईं, वहां सीटें गंवाएंगी। वहीं, फायदे वाली पार्टियां एनडीए दल की हो सकती हैं। इनमें बीजेपी को 7-9 सीटों का फायदा हो सकता है यानी कुल एनडीए 145 तक पहुंच सकती है। कांग्रेस को डीएमके तमिलनाडु में 1-2 एक्स्ट्रा सीट का फायदा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इंडिया गठबंधन डाउन रहेगा। महाराष्ट्र में 7 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है, जिसमें से एनडीए के 6 सीटें मिल सकती है तो विपक्षी गठबंधन महायुति के सिर्फ एक सीट मिलने की संभावना है। राज्य में कुल 286 विधानसभा सीटें है, जिसमें से 2 सीटें खाली हैं। इस लिहाज से एक राज्यसभ सीट के लिए 37 विधायकों के समर्थन की जरूरत है।

मौजूदा समय में बीजेपी के पास 131, शिंदे की शिवसेना के पास 57 और अजित पवार की एनसीपी के पास 40 विधायक हैं। एनडीए के 235 विधायक बन रहे हैं, जिसके दम पर 6 सीटें आसानी से जीत सकती है। बीजेपी चार सीटें तो शिंदे और अजित पवार की पार्टी को एक-एक सीट जीत सकती है। शरद पवार की एनसीपी के 10, उद्धव ठाकरे की 16 और कांग्रेस के 20 विधायक हैं। इस तरह से तीनों दलों के कुल 46 विधायक। सीपीआई (एम) और एसके (एम) का एक-एक विधायक है। अन्य छोटे दलों और निर्दलीयों का समर्थन मिलने पर यह संख्या कुछ बढ़ सकती है। ऐसे में एक सीट विपक्ष मिलकर सकती है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में से किसी एक दल को की यह सीट मिल सकती है, जिसके चलते शरद पवार की सीटें और उद्धव ठाकरे के लिए सियासी नुकसान होगा।बिहार की पांच राज्यसभा सीट पर चुनाव होने हैं, जिसमें एनडीए आसानी से 4 सीटें जीत सकती है और एक सीट विपक्ष को मिल सकती है। तमिलनाडु में की मौजूदा विधानसभा की स्थिति के लिहाज से डीएमके आसानी से चार सीटें जीत लेगा और एक सीट एआईएडीएमके भी बचा ले जाएगा, लेकिन एक सीट पर मुकाबला हो सकता है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल की पांच सीटों में से टीएमसी अपनी चारों सीटें बचा लेगा, लेकिन यहां पर एक सीट सीपीएम को खोनी पड़ सकती है, जो बीजेपी के खाते में जा सकती है। ओडिशा में चार सीटों में से बीजेपी 3 सीटें आसानी से जीत लेगी और एक सीट से बीजेडी को संतोष करना पड़ सकता है।

एनसीपी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार, अभिषेक मनु सिंघवी और प्रियंका चतुर्वेदी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके अलावा राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह से लेकर उपेंद्र कुशवाहा का भी टर्म पूरा हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (कर्नाटक) के लिए री-इलेक्शन की कोशिश हो रही है, लेकिन स्पेकुलेशन है कि वह नहीं लौटेंगे। दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश) को कमलनाथ की जगह थर्ड टर्म नहीं मिलेगा। एचडी देवगौड़ा (कर्नाटक) जेडीएस के पास नंबर नहीं है इसलिए रिटायरमेंट संभव है। शरद पवार (महाराष्ट्र) टर्म एंड, एनसीपी शरद पवार कमजोर, रंजन गोगोई (नॉमिनेटेड) मार्च में रिटायर, परिमल नथवानी (आंध्र) बीजेपी सेकंड टर्म नहीं देगी, बिकाश रंजन भट्टाचार्य सीपीआई एम। ऐसे में देखना है कि इन दिग्गज नेताओं में से किसकी वापसी होती है, इसके अलावा किस दल को किसे फायदा और किसे नुकसान होगा। कुल मिलाकर, 2026 राज्यसभा में एनडीए और मजबूत होगा, जो विधेयकों पास करने में आसानी देगा। विपक्ष को रणनीति बदलनी पड़ेगी।

नजरिया

डिजिटल युग में मातृभाषाओं को बचाना बड़ी चुनौती

ललित गर्ग

मोबाइल : 9811051133

21 फरवरी को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस केवल मातृभाषा संस्कृति को बचाने का अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि मानवता की सांस्कृतिक आत्मा का उत्सव है। वर्ष 2026 में इसकी मुख्य थीम बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज़ है, जो यह संकेत देती है कि भविष्य की भाषाई दिशा युवा पीढ़ी तय करेगी। यह वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस दिवस की 25वीं वर्षगांठ-रजत जयंती का प्रतीक है। वर्ष 1999 में यूनेस्को द्वारा इसकी घोषणा की गई और 2000 से इसे वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। इस वर्ष का फोकस 13 से 18 वर्ष के युवाओं को भाषाई विविधता के संरक्षण, मातृभाषा में शिक्षा के विस्तार और डिजिटल युग में भाषाओं की भूमिका पर सक्रिय संवाद के लिए प्रेरित करना है। मातृभाषा केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती, वह मनुष्य के मन, मस्तिष्क और संवेदनाओं की प्रथम अभिव्यक्ति है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह किसी औपचारिक शिक्षा से पहले अपनी माँ की ध्वनियों, लोरियों और संवादों के माध्यम से भाषा का संस्कार ग्रहण करता है। यही भाषा उसकी सोच, उसकी रचनात्मकता और उसकी पहचान का आधार बनती है। शोधों से यह सिद्ध हो चुका है कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होने पर बच्चों की समझ, विश्लेषण क्षमता और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। फिर भी वैश्विक स्तर पर लगभग 40 प्रतिशत बच्चों को उस भाषा में शिक्षा नहीं मिलती जिसे वे बोलते या समझते हैं।

इस दिवस का ऐतिहासिक संदर्भ हमें 21 फरवरी 1952 की उस त्रासदी की याद दिलाता है जब पूर्वी पाकिस्तान में अपनी मातृभाषा बांग्ला के सम्मान के लिए छात्रों ने आंदोलन किया और गोलीबारी में अनेक युवा शहीद हो गए। बाद में यही पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश बना। उन शहीदों की स्मृति में यह दिवस भाषाई अधिकारों और अस्मिता का प्रतीक बन गया। यह हमें सिखाता है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता का आधार है। वर्ष 2026 की थीम युवाओं की भागीदारी को केंद्र में रखती है। आज का युवा डिजिटल संसार में जी रहा है। सोशल मीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑनलाइन शिक्षा उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मातृभाषाओं के लिए पर्याप्त स्थान है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ओर तो विलुप्तप्राय भाषाओं के शब्दकोश, ध्वनि-संग्रह और अनुवाद प्रणाली विकसित कर उन्हें पुनर्जीवित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर यदि तकनीक कुछ सीमित भाषाओं तक सिमट जाए तो भाषाई असमानता और गहरी हो सकती है। इसलिए युवाओं को तकनीक का उपयोग मातृभाषा सशक्तिकरण के लिए करना होगा-ऐप, ब्लॉग, पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल और डिजिटल पुस्तकालयों के माध्यम से अपनी भाषाओं को वैश्विक मंच देना होगा।

यूनेस्को का मानना है कि स्थायी समाज के लिए सांस्कृतिक और भाषाई विविधता बहुत जरूरी है। शांति के लिए अपने जनादेश के तहत यह संस्कृतियों और भाषाओं में अंतर को बनाए रखने के लिए काम करता है जो दूसरों के लिए सहिष्णुता और सम्मान को बढ़ावा देते हैं। बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक समाज अपनी भाषाओं के माध्यम से अस्तित्व में रहते हैं जो पारंपरिक ज्ञान और संस्कृतियों को स्थायी तरीके से प्रसारित और संरक्षित करते हैं। भाषाई विविधता लगातार खतरे में पड़ती जा रही है क्योंकि अधिकाधिक भाषाएं लुप्त होती जा रही हैं। मातृभाषा जीवन का आधार है, यह एक ऐसी भाषा होती है जिसे सीखने के लिए उसे किसी कक्षा की जरूरत नहीं पड़ती। जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं, वही व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। लेकिन मानव समाज में कई दफा हमें मानवाधिकारों के हनन के साथ-साथ मातृभाषा के उपयोग को गलत भी बताया जाता रहा है।

भारत जैसे बहुभाषी देश में यह चुनौती और अवसर दोनों है। पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार पिछले कुछ दशकों में सैकड़ों भाषाएँ लुप्त हो चुकी हैं। यह केवल शब्दों का खो जाना नहीं, बल्कि परंपराओं, लोककथाओं, लोकगीतों और जीवनदृष्टि का विलुप्त होना है। यदि नई पीढ़ी अपनी मातृभाषा से विमुख हो जाएगी तो सांस्कृतिक जड़ों से उसका संबंध कमजोर हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में बहुभाषी शिक्षा को प्रोत्साहन मिले, स्थानीय साहित्य और लोकसंस्कृति को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए, और युवाओं को अपनी भाषा में अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए जाएँ। आज एक बड़ा भ्रम यह है कि केवल विदेशी भाषा ही विकास का मार्ग है। निस्संदेह वैश्विक संपर्क के लिए अन्य भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपनी मातृभाषा की उपेक्षा कर। मातृभाषा में शिक्षा से ही मौलिक चिंतन और नवाचार संभव है। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 ने भी प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने पर बल दिया है। यह निर्णय वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित है, क्योंकि जब विद्यार्थी अपनी सहज भाषा में सीखता है तो वह केवल जानकारी ग्रहण नहीं करता, बल्कि उसे आत्मसात करता है।

हमारे देश में मातृभाषाओं के प्रति अनेक प्रकार के भ्रम फैले हैं, जिनमें एक भ्रम है कि अंग्रेजी विकास और ज्ञान की भाषा है। जबकि इस बात से यूनेस्को सहित अनेक संस्थानों के अनुसंधान यह सिद्ध कर चुके हैं कि अपनी भाषा में शिक्षा से ही बच्चे का सही एवं सर्वांगीण मायने में विकास हो पाता है। इस दृष्टि से मातृभाषा में शिक्षा पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। युवाओं में मातृभाषा के प्रति आकर्षण कैसे बढ़ाया जाए? पहला उपाय है-भाषा को बोझ नहीं, गौरव के रूप में प्रस्तुत करना। जब हम अपने साहित्यकारों, वैज्ञानिकों और महापुरुषों की उपलब्धियों को मातृभाषा से जोड़कर बताते हैं, तो युवाओं में स्वाभिमान जागृत होता है। दूसरा उपाय है-रचनात्मक मंच उपलब्ध कराना। कविता-पाठ, नाटक, वाद-विवाद, ब्लॉग लेखन और डिजिटल कंटेंट निर्माण के माध्यम से युवा अपनी भाषा में सृजन कर। तीसरा उपाय है-परिवार की भूमिका। घर में यदि संवाद मातृभाषा में होगा तो बच्चे में स्वाभाविक अनुराग उत्पन्न होगा। भाषाई विविधता के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना भी उतना ही आवश्यक है। भारत में सैकड़ों भाषाएँ और बोलियाँ हैं; प्रत्येक भाषा अपने साथ एक विशिष्ट जीवनदर्शन लेकर आती है। हमें यह समझाना होगा कि किसी भी भाषा को छोटा या बड़ा कहना अनुचित है। सभी भाषाएँ समान रूप से सम्माननीय हैं। हिन्दी राजभाषा है, परंतु अन्य भारतीय भाषाएँ भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। संस्कृत हमारी प्राचीन ज्ञान-परंपरा की धरोहर है, तो तमिल, बांग्ला, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमिया, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, कश्मीरी और अन्य भाषाएँ अपनी-अपनी सांस्कृतिक संपदा से राष्ट्र को समृद्ध करती हैं।

डिजिटल युग में युवाओं को यह संकल्प लेना चाहिए कि वे अपनी मातृभाषा में कम से कम एक रचनात्मक कार्य अवश्य करेंगे-चाहे वह एक ब्लॉग हो, एक कहानी, एक गीत या एक शैक्षिक वीडियो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद उपकरणों और भाषा मॉडल्स का उपयोग करके वे अपनी भाषा की सामग्री को वैश्विक पाठकों तक पहुँचा सकते हैं। इससे न केवल भाषा का संरक्षण होगा, बल्कि आर्थिक अवसर भी बढ़ेंगे। स्थानीय भाषाओं में स्टार्टअप, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और डिजिटल प्रकाशन नए रोजगार के द्वार खोल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2026 हमें यह संदेश देता है कि भाषाई विविधता ही मानवता की वास्तविक समृद्धि है।

यदि हम सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो समावेशी शिक्षा आवश्यक है, और समावेशी शिक्षा का आधार मातृभाषा है। युवाओं की आवाज़ जब बहुभाषी शिक्षा के समर्थन में उठेगी, तभी समाज में व्यापक परिवर्तन संभव होगा। आज आवश्यकता है एक सामूहिक संकल्प की-हम अपनी मातृभाषा का सम्मान करेंगे, उसे डिजिटल मंचों पर प्रतिष्ठित करेंगे और आने वाली पीढ़ियों तक उसकी विरासत पहुँचाएँगे। भाषा हमारी आत्मा है; उसे जीवित रखना हमारा दायित्व है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर यही संदेश गूंजना चाहिए कि युवा ही भाषाई भविष्य के प्रहरी हैं। जब युवा अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, तभी विश्व अधिक समावेशी, सहिष्णु और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनेगा।

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- दक्षिण भारत राष्ट्रमत

होली

पटना के मगध महिला कॉलेज में होली मिलन सेलिब्रेशन में स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया।

भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले रणनीति गठजोड़ 'पैक्स सिलिका' में शामिल हुआ

नई दिल्ली/भाषा। भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले रणनीतिक गठजोड़ 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है।यहां नई दिल्ली में 'एआई इम्पैक्ट समिट' में आयोजित एक समारोह में गठबंधन में शामिल होने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।वहां उपस्थित लोगों में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, आर्थिक मामलों के लिए अमेरिकी उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर शामिल थे।यह कदम दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और संबंधों में गंभीर तनाव के दौर के बाद द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई अन्य पहलों पर आगे बढ़ने के प्रयासों के बीच आया है।गोर ने अपनी टिप्पणी में कहा, ''व्यापार समझौते से लेकर पैक्स सिलिका और रक्षा सहयोग तक, दोनों देशों की साथ काम करने की संभावनाएं वास्तव में असीमित हैं।'' अमेरिकी राजदूत ने कहा कि पैक्स सिलिका में भारत का प्रवेश केवल एक प्रतीकात्मक कदम नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक कदम है जो द्विपक्षीय संबंधों की समग्र दिशा को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा, ''भारत ऐसा देश है जहां प्रतिभा का भंडार है, जो प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती देने के लिए काफी है। भारत की इंजीनियरिंग क्षमता इस महत्वपूर्ण गठबंधन के लिए आवश्यक योग्यताएं प्रदान करती है। प्रतिभा के अलावा, भारत ने महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण क्षमता की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति की है और हम इसमें भी पूरी तरह से सहभागिता कर रहे हैं।''

गोर ने सुझाव दिया कि अमेरिका पैक्स सिलिका ढांचे के तहत भारत के साथ विश्वसनीय एआई प्रौद्योगिकियां साझा कर सकता है।

अमेरिकी उप विदेश मंत्री हेलबर्ग ने गठबंधन में शामिल होने के भारत के फैसले की सराहना की और पैक्स सिलिका को आपूर्ति श्रृंखलाओं में दबाव की रणनीति और ब्लैकमेल के खिलाफ एक पहल बताया, जिसे चीन की ओर एक स्पष्ट इशारा माना जा रहा है। स्त्र

उन्होंने कहा, ''हम देखते हैं कि हमारे मित्र और सहयोगी प्रतिदिन आर्थिक दबाव और ब्लैकमेल के खतरों का सामना कर रहे हैं। उन्हें अपनी संप्रभुता और अपनी समृद्धि के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हम खुद को एक ऐसी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जूझते हुए पाते हैं जो अत्यधिक केंद्रित है।'' उन्होंने कहा, ''इसलिए आज, जब हम पैक्स सिलिका घोषणा पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, तो हम बतौर 'हथियार', प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को ना कहते हैं, हम ब्लैकमेल को ना कहते हैं और हम मिलकर कहते हैं कि आर्थिक सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा है, लेकिन हमें इस शब्द के अर्थ के बारे में स्पष्ट होना चाहिए।''

मानव जैसे घरेलू रोबोट बाजार में, लेकिन क्या हम सचमुच उन्हें अपने घर में चाहते हैं?

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

सिडनी। पिछले वर्ष नॉर्वे-अमेरिका की प्रौद्योगिकी कंपनी वनएक्स ने एक अनोखे उत्पाद की घोषणा की दुनिया का पहला मानवनुमा रोबोट, जो घरेलू जीवन को बदलने के लिए बनाया गया है। कुल 168 सेंटीमीटर लंबा और 30 किलोग्राम वजनी 'नियो' नामक इस रोबोट की कीमत लगभग 20,000 अमेरिकी डॉलर है और यह कपड़े तह करने और बर्तन धोने जैसी घरेलू गतिविधियों को स्वचालित ढंग से करने का दावा करता है।

नियो में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रणाली अंतर्निहित है, लेकिन जटिल कार्यों के लिए कंपनी का एक कर्मचारी वर्चुअल रियलिटी हेलमेट पहनकर उसे दूरस्थ रूप से नियंत्रित करता है। इस दौरान ऑपरेटर घर के भीतर, रोबोट जो भी देखता है, उसे देख सकता है और यह प्रक्रिया भविष्य में सीखने के लिए रिकॉर्ड भी की जाती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस वर्ष अन्य घरेलू मानवनुमा रोबोट भी बाजार में आ सकते हैं। हालांकि, नियो उन चुनौतियों को उजागर करता है जो हालिया एआई उछाल में देखने को मिली हैं भारी प्रचार के साथ सीमित क्षमताओं वाले उत्पाद, गोपनीयता से जुड़े छिपे जोखिम और पर्दे के पीछे काम कर रहे अदृश्य दूरस्थ कर्मचारी।

मानव जैसी मशीनों की कल्पना प्राचीन मिथकों से जुड़ी रही है, लेकिन उन्हें व्यावहारिक उपभोक्ता उत्पाद के रूप में देखना अपेक्षाकृत नया विचार है। विश्वभर में 50 से अधिक कंपनियां ऐसे रोबोट विकसित कर रही हैं। हाल के वर्षों में बैटरी, मोटर और सेंसर जैसे हार्डवेयर में सुधार विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की प्रगति और उन्नत एआई प्रणालियों से इस दिशा में तेजी आई है।

बाधाएं फिर भी बनी हुई हैं। घर, अस्पताल या अन्य अनियंत्रित वातावरण में रोजमर्रा के काम करना अभी भी रोबोट के लिए कठिन है। वैक्यूम क्लीनर जैसे विशेष रोबोट तो आम हो गए हैं, परंतु मानव घरों का ढांचा रोबोट के अनुकूल नहीं है। कई सूक्ष्म कार्यों में विशेष मशीनें बेहतर परिणाम देती हैं।

रोबोट के प्रदर्शन को सुधारने के लिए वास्तविक दुनिया के विस्तृत आंकड़ों की आवश्यकता होगी, जो लोगों के घरों में काम करते समय एकत्र होंगे। इससे निजी जीवन से जुड़े संवेदनशील डेटा के संग्रहण का खतरा बढ़ता है और गोपनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। इसके अलावा, तकनीकी उद्योग में बढ़ते दूरस्थ ऑनलाइन श्रम से सामाजिक-आर्थिक असमानता और कम वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों के शोषण जैसी चिंताएं भी जुड़ी हैं।

'इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स' के अनुसार, व्यापक रूप से स्वीकार्य और उपयोगी घरेलू मानवनुमा रोबोट आने में अभी लगभग 20 वर्ष लग सकते हैं। वहीं जापानी शोधकर्ता हिरोशी इशिगुरो दशकों से मानव-सदृश 'जेमिनॉइड' बना रहे हैं, जिनका उद्देश्य केवल सुविधा या मुनाफा नहीं बल्कि यह समझना है कि मानव होने का मतलब क्या है।

पर्सनैलिटी राइट प्रोटेक्शन : बिना इजाजत काजोल की फोटो-वीडियो इस्तेमाल करना अपराध

मुंबई/एजेन्सी

साल 2025 में बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने पर्सनैलिटी राइट्स के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन अब उनकी पत्नी काजोल के लिए भी कोर्ट ने पर्सनैलिटी राइट का प्रोटेक्शन दिया है। पर्सनैलिटी राइट्स को सुरक्षा देते हुए कोर्ट ने साफ किया है कि अब बिना अनुमति के अभिनेत्री के नाम, फोटो और वीडियो का इस्तेमाल करना अपराध होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने पर्सनैलिटी राइट के प्रोटेक्शन का आदेश देते हुए अभिनेत्री के विरुद्ध प्रकाशित अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने एआई और डीपफेक जैसी तकनीकों के माध्यम से काजोल के नाम, छवि अथवा व्यक्तित्व के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उच्च न्यायालय ने विभिन्न प्रतिवादी संस्थाओं को यह भी निर्देश दिया कि वे काजोल की तस्वीर या पहचान का प्रयोग कर किसी भी प्रकार के व्यावसायिक उत्पादों की बिक्री न करें। साथ ही अश्लील सामग्री को हटाने का आदेश दिया है। एआई और डीपफेक के जरिए इन दिनों सोशल मीडिया पर अवैध तरीके से उत्पादों के प्रचार और अश्लील साइटों पर अभिनेता और अभिनेत्रियों की तस्वीरों का इस्तेमाल बढ़ गया है। कुछ साइट बिना इजाजत के धड़ल्ले से एआई की आड़ में सेलिब्रिटीज की वीडियो का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा, भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए डीपफेक फोटो और वीडियो का भी चलन बढ़ गया है। ऐसे में इसे किसी भी अभिनेता या अभिनेत्री की छवि पर सीधा हमला माना गया है। अभिनेता विवेक ओबरॉय के मामले में कोर्ट ने साफ कहा था कि तकनीक का इस्तेमाल कर किसी की छवि को नुकसान पहुंचाना भी अपराध है। काजोल के अलावा, अजय देवगन ने भी बीते साल पर्सनैलिटी राइट्स के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी।

कोर्ट ने अभिनेता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सभी अवैध साइट और एआई-जनरेटेड डीपफेक वीडियो को हटाने का आदेश दिया था और आगे भी इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। पर्सनैलिटी राइट्स के मामले में हिंदी सिनेमा से लेकर दक्षिण भारतीय सिनेमा के सेलेब्स कोर्ट का रुख कर चुके हैं।

'वीरा राजा वीरा' विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, एआर रहमान बोले- गाने में जूनियर डागर ब्रदर्स को मिलेगा क्रेडिट

नई दिल्ली/एजेन्सी

मशहूर संगीतकार एआर रहमान पर तमिल फिल्म 'पोन्नियिन सेलवन 2' के लोकप्रिय गीत 'वीरा राजा वीरा' से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। एआर रहमान ने शुक्रवार को अदालत को बताया कि इस गाने को वह भारतीय शास्त्रीय संगीत की पारंपरिक रचना 'शिव स्तुति' से प्रेरित मानते हुए क्लासिकल सिंगर उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर को श्रेय देने के लिए तैयार हैं। रहमान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया कि संगीतकार ने यह सहमति दी है कि गीत के क्रेडिट में दिवंगत उस्ताद एन. फैयाजुद्दीन डागर और उस्ताद एन. जाहिरुद्दीन डागर, जिन्हें जूनियर डागर ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, उनके प्रदर्शन का उल्लेख किया जाएगा। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली शामिल थे, ने की। अदालत ने रहमान की ओर से दी गई इस सहमति को रिकॉर्ड में लेते हुए आदेश दिया कि गाने के क्रेडिट में किया गया बदलाव सभी सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर पांच हफ्तों के भीतर दिखना चाहिए। अदालत ने साफ किया कि यह मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा सिविल मुकदमा अपने तथ्यों और कानून के आधार पर ही आगे बढ़ेगा।

'तन्वी द ग्रेट' को लेकर अनुपम खेर की नई अनाउंसमेंट, ओटीटी पर जल्द रिलीज होगी फिल्म

मुंबई/एजेन्सी

'आइकॉनिक गोल्ड अवॉर्ड' में फिल्मी और टीवी जगत के सितारों को सम्मानित किया गया। हिंदी सिनेमा में 550वीं फिल्म कर रहे अनुपम खेर को अपनी सबसे खास फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' के लिए अवॉर्ड से नवाजा गया। अब उन्होंने फिल्म की पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए खुशी जाहिर की है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनके द्वारा निर्देशित की गई फिल्म को इतना सम्मान मिल रहा है, हालांकि खुद अभिनेता ने फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है। अनुपम खेर द्वारा निर्देशित फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' को पहले भी बहुत सारे अवॉर्ड मिल चुके हैं। अब फिल्म के खाते में 'आइकॉनिक गोल्ड अवॉर्ड' का नाम भी जुड़ गया है। इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सम्मान मिला है और फिल्म में तन्वी का रोल प्ले करने वाली अभिनेत्री को बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला है।

'तन्वी द ग्रेट' अभिनेता के करियर की सबसे खास फिल्म है क्योंकि फिल्म की कहानी उनकी भांजी से प्रेरित है, जो कि ऑटिज्म से पीड़ित है। अनुपम खेर ने कई बार अपनी भांजी को सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से मिलाया है। फैन उनके सिंगिंग टैलेंट को देखकर भी हैरान हैं। अभिनेता ने इसी कहानी को पर्दे पर 'तन्वी द ग्रेट' के जरिए पेश किया और फिल्म को डायरेक्ट भी किया।

अभिनेता ने अवॉर्ड नाइट्स की फोटो पोस्ट की और अपनी खुशी को शब्दों में बयां करने की कोशिश भी की। उन्होंने लिखा, यह हम सभी के लिए एक बेहद खुशी का पल है, जिन्होंने साहस, अच्छाई और शांत शक्ति की इस कहानी पर विश्वास किया। पुरस्कार तो खूबसूरत होते हैं। लेकिन, असली मायने तो सफर के हैं। रिहर्सल, शंकाएं, आंसू, हंसी, और उस टीम का अटूट विश्वास, जो एक परिवार की तरह साथ खड़ी रही।

अभिनेता ने कैप्शन में फिल्म की पूरी टीम चाहे वो पर्दे के सामने काम करने वाले कलाकार हों या फिर पर्दे के पीछे, सबको अवॉर्ड का हकदार बताया। अनुपम खेर का कहना है कि ये फिल्म सिर्फ एक शुरुआत है और सफर बहुत लंबा होना है। जैसे तन्वी ने लोगों के दिलों में जगह बनाई, वैसे ही कई और फिल्में भी पर्दे पर आएंगी। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि फिल्म जल्द ही ओटीटी पर रिलीज की जाएगी। हालांकि प्लेटफॉर्म और रिलीज की डेट क्या होगी, यह तो आगे आने वाला समय ही बताएगा।

30 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी मामले में विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को मिली जमानत

मुंबई/एजेन्सी

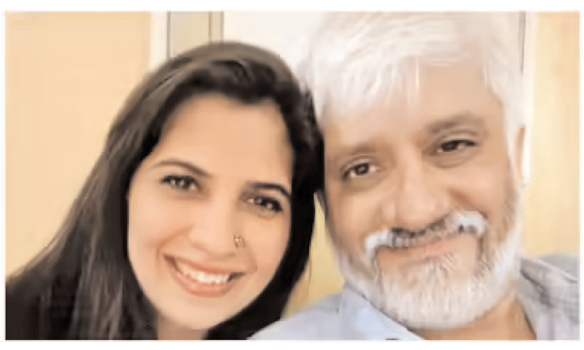

30 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मामले में विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेताम्बरी भट्ट को सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है और साथ ही दोनों पक्षों को मध्यस्थता के जरिए मामले को सुलझाने की सलाह दी है। इससे पहले 13 फरवरी को मामले को लेकर हुई सुनवाई में पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दंपत्ति को मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत दी थी और कहा था कि जेल में बंद करके पैसे की रिकवरी नहीं की जा सकती है और साथ ही राजस्थान पुलिस को मामले में नोटिस भी जारी किया था। गुरुवार को कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए दंपत्ति को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन जमानत के दिशा-निर्देश उदयपुर कोर्ट ही तय करेगा। बता दें कि 7 दिसंबर से जेल में बंद विक्रम भट्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट में जमानत याचिका डाली थी, लेकिन वहां से राहत न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

30 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में आरोप है कि भट्ट दंपति ने शिकायतकर्ता को उसकी दिवंगत पत्नी के जीवन पर बनने वाली बायोपिक और तीन अन्य फिल्मों के लिए 30 करोड़ से अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित किया था और उन्हें इसके एवज में अच्छे मुनाफे का भरोसा दिया था, जो पूरा नहीं हुआ।

कुछ फिल्मों की शूटिंग हुई, लेकिन बाकी फिल्में ठंडे बस्ते में रहीं। पैसे वापस मांगने पर इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक डॉक्टर अजय मुर्डिया के साथ भट्ट दंपत्ति टालमटोल करने लगे। आखिर में उन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा।बता दें कि इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक डॉक्टर अजय मुर्डिया उदयपुर और देश के बाकी राज्यों में आईवीएफ सेंटर चलाते हैं। उन्होंने सबसे पहले उदयपुर से ही बिजनेस की शुरुआत की थी। संस्थापक चाहते थे कि उनकी दिवंगत पत्नी की बायोपिक बने और उसी के लिए वे विक्रम भट्ट के संपर्क में आए थे। 30 करोड़ के अलावा विक्रम भट्ट और उनकी बेटी 13.5 करोड़ के एक अन्य धोखाधड़ी के केस में लिप्त हैं, जहां एक बिजनेसमैन ने उन पर निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है।

क्या द वार्डरोब में दिव्या अग्रवाल निभा रही हैं भूत का किरदार?

मुंबई/एजेन्सी

राज गवली प्रोडक्शन ने अपनी आगामी सुपरनैचुरल थ्रिलर ढ्ढह्वश थरीवीलश का दिलचस्प फर्स्ट-लुक पोस्टर जारी कर दिया है, और फैंस अब यह सवाल पूछ रहे हैं क्या उ्ळ्रीूर -सरीुरश्र इस फिल्म में भूत का किरदार निभा रही हैं? सौरभ चौबे के निर्देशन में बनी इस हॉरर थ्रिलर में ठरक्षपळशीह ऊर्ीससरश्रश्र भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। पोस्टर में एक रहस्यमयी महिला को पुराने, आधे खुले लकड़ी के वार्डरोब से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है, जिस पर लताएं लिपटी हुई हैं। खून से सने सफेद गाउन में और धुएं व अंधेरे से घिरे माहौल के बीच दिव्या का डरावना अंदाज़ उनके किरदार को लेकर कई सवाल खड़े करता है। वार्डरोब के भीतर से आती लाल रोशनी फिल्म के सुपरनैचुरल टोन को और गहरा करती है, जिससे दर्शकों की उत्सुकता बढ़ गई है। हालांकि मेकर्स ने कहानी के अहम पहलुओं को अभी गोपनीय रखा है, लेकिन पोस्टर ने इस बात की अटकलों को हवा दे दी है कि दिव्या किसी बेचैन आत्मा की भूमिका में हो सकती हैं।

मेरे पास फिल्मों के ऑफर आते रहते हैं : अमृता फडणवीस

मुंबई/एजेन्सी

प्लेबैक सिंगर और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस इन दिनों अपने नए भक्ति गीत 'शंभू रे' को लेकर चर्चाओं में हैं। उनके इस गीत को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए अपने संगीत सफर के बारे में बताया। साथ ही अभिनय क्षेत्र में कदम रखने के सवाल पर भी सटीक जवाब दिया। आईएएनएस ने अमृता फडणवीस से सवाल किया कि वह मनोरंजन जगत से काफी नजदीक से जुड़ी हैं, ऐसे में क्या उन्होंने कभी एक्टिंग करने के बारे में सोचा है? इस पर उन्होंने बताया, ''मुझे कई बार फिल्मों के ऑफर आते रहे हैं। लेकिन, हर बार मैंने इन ऑफर्स को विनम्रता के साथ मना किया है। मेरा मानना है कि हर इंसान का जीवन में एक रास्ता तय होता है और अभिनय मेरा रास्ता नहीं है। संगीत मेरा पहला और आखिरी प्यार है। यह वह कला है जो मुझे स्वाभाविक रूप से आती है और इसमें मैं खुद को पूरी तरह व्यक्त कर पाती हूं। मैं वही काम करना चाहती हूं, जिससे मैं पूरी ईमानदारी से जुड़ी रहूं और वह काम मेरे लिए संगीत ही है।''

अपने पैशन के बारे में बात करते हुए अमृता ने कहा, ''संगीत मेरे लिए सांस लेने जैसा है। जिस तरह इंसान बिना सांस के नहीं रह सकता, उसी तरह मैं संगीत के बिना खुद को अधूरा महसूस करती हूं। चाहे देर रात हो या सुबह का सुकून भरा वक्त, जब भी समय मिलता है, मैं शास्त्रीय संगीत का अभ्यास करती हूं। सुरों की साधना और रियाज मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है।'' गौरतलब है कि 14 फरवरी को रिलीज हुआ भक्ति गीत 'शंभू रे' बेहद कम समय में दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बना चुका है। इस गीत को अब तक 9 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। अमृता फडणवीस की आवाज में 'शंभू रे' का संगीत मोटी शर्मा ने तैयार किया है, जिन्होंने सुरों के जरिए शिवभक्ति को नई गहराई दी है। वहीं, गीत के बोल सृजन विनय वैष्णव ने लिखे हैं। गाने का निर्देशन राजीव वालिया ने किया है और इसे भगवान शिव से जुड़े '27 पवित्र स्थलों' पर फिल्माया गया है।

'घूसखोर पंडत' विवाद पर विराम, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का किया निपटान

मुंबई/एजेन्सी

पोस्टर रिलीज के साथ विवादों में घिरी फिल्म 'घूसखोर पंडत' मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केस का निपटारा कर दिया है। शीर्ष अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि फिल्म को लेकर कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी और न ही किसी याचिका पर सुनवाई होगी। गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिल्ममेकर्स को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किया है कि अब 'घूसखोर पंडत' से जुड़े विवाद को बंद किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने किसी नई याचिका पर भी सुनवाई से इनकार किया। इसके साथ ही फिल्म मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि फिल्म मेकर्स और प्रोडक्शन हाउस का किसी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। फिल्म एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा है, जो एक अपराध की जांच पर आधारित है। फिल्म में किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या संप्रदाय को भ्रष्ट नहीं दिखाया गया है। हफलनामें में दावा किया गया कि फिल्म का पुराना नाम 'घूसखोर पंडत' वापस ले लिया गया है और नया नाम अभी तय नहीं हुआ है। साथ ही सभी प्रचार सामग्री, पोस्टर और ट्रेलर वापस ले लिए गए हैं।इससे पहले मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म मेकर्स को कड़ी फटकार लगाई थी और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी वर्ग को निशाना बनाने पर लताड़ा भी था।कोर्ट ने साफ-साफ कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी वर्ग विशेष को नीचा दिखाएं। कोर्ट के आदेश के बाद ही अभिनेता मनोज बाजपेयी की फिल्म से जुड़े पोस्टर्स और प्रचार सामग्री को तुरंत प्रभाव से हटा लिया गया था। हालांकि, नया नाम क्या होने वाला है, इस पर सस्पेंस बरकरार है। विवाद को लेकर फिल्म स्टार्स और मेकर्स दोनों सोशल मीडिया पर सफाई भी दे चुके हैं। अभिनेता मनोज बाजपेयी ने भी कहा था कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि सिर्फ मनोरंजन करना है। उन्होंने पोस्ट के जरिए सभी से माफी भी मांगी थी और फिल्म का शीर्षक बदलने की जानकारी भी दी थी।

कोयम्बटूर उड़ान यात्री कैफे का हुआ शुभारंभ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोयम्बटूर। केन्द्र सरकार की योजनाओं में से एक 'उड़ान यात्री कैफे', एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों को सस्ते दामों पर चाय और नाश्ता का कैफे; का उद्घाटन किया गया। सात ही कोयम्बटूर कोरा कॉटन गारमेन्ट शॉप का भी शुभारंभ किया गया। एयरपोर्ट में यात्रियों के बच्चों के लिए छोटा सा खेलने का कॉर्नर बनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री राम मोहन नायडू, केन्द्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहाल, एल मुरुगन, विधायक वनाति श्रीनिवासन आदि ने किया। नागरिक उड्डन के सचिव समीर कुमार सिन्हा, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन विपिन कुमार सहित अनेक गणमान्य उपस्थित थे।

राणी दादी का फाल्गुन महोत्सव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तिरुपुर। दादी परिवार द्वारा हर महीने कि भांति इस महीने भी दादी परिवार कि ओर से राणी सती दादी का फाल्गुन महोत्सव मंगल पाठ गणेश मन्दिर रायपुरम में सुबह 11, बजे गणेश वन्दना के साथ चालू किया गया और दोपहर 2 बजे महाआरती एवं महाप्रसाद दादी के मंगल पाठ के इस कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया । उसके उपरांत कार्यक्रम मे आये सभी महिलाओं ने मिलकर आपस में दादी को मीठे-मीठे होली उत्सव के भजनों से रिझाया।

इस्कॉन चेन्नई द्वारा होलिका दहन 2 मार्च को

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। सोलिंगनलूर स्थित इस्कॉन मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी होलिका दहन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस्कॉन चेन्नई के सदस्य सुरेश कुमार सांघी ने बताया है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य भक्तों को आध्यात्मिक लाभ प्रदान करना एवं श्री कृष्ण एवं भक्त प्रह्लाद की गौरवमई लीलाओं का स्मरण कराना है । कार्यक्रम का शुभारंभ दोपहर 12 बजे से होगा तथा रात्रि के 7:30 बजे होलिका दहन भक्तों की उपस्थिति में किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों में इस्कॉन मंदिर के अनेक पदाधिकारी गण लगे हुए है।

एआर रहमान ने जूनियर डागर बंधुओं को गाने का श्रेय देने पर सहमति जताई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/नई दिल्ली। संगीतकार एआर रहमान ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि वह तमिल फिल्म 'पोन्नियिन सेल्वन : 2' के 'वीरा राजा वीरा...' गाने का श्रेय जूनियर डागर बंधुओं को देने के लिए तैयार हैं। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने विवाद में शामिल हस्तियों को संगीत जगत का प्रतिष्ठित नाम बताया। पीठ ने रहमान की दलीलें दर्ज कर याचिका का निपटारा कर दिया। रहमान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने पीठ से कहा कि उनके मुवक्किल जूनियर डागर बंधुओं को गाने का श्रेय देंगे।

सिंघवी ने कहा कि गाने के बारे में लिखा होगा - ध्रुपद गायन की डागरवानी परंपरा से प्रेरित रचना, जिसे जूनियर डागर बंधुओं के नाम से मशहूर दिवंगत उस्ताद नासिर फैयाजुद्दीन डागर और उस्ताद नासिर जहीरुद्दीन डागर ने पहली बार 'शिव स्तुति' के रूप में रिकॉर्ड किया था। शीर्ष अदालत ध्रुपद गायक उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय के सितंबर 2025 के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि जूनियर डागर बंधुओं के 'शिव स्तुति' के शास्त्रीय स्वरूप के लेखक होने का प्रथम दृष्टया कोई सबूत नहीं है। पीठ ने संशोधित 'क्रेडिट' सभी सोशल मीडिया और ओटीटी मंचों पर पांच सप्ताह के भीतर दिखाने को कहा।

शीर्ष अदालत ने रहमान को निर्देश दिया कि वह उच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित दो करोड़ रुपये की राशि अंतरिम रूप से रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा करें। पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने कोई राय व्यक्त नहीं की है और पक्षों के बीच लंबित दीवानी मुकदमा उसके आदेश से अप्रभावित रहते हुए आगे बढ़ेगा। उच्चतम न्यायालय ने 13 फरवरी को याचिका पर सुनवाई करते हुए रहमान और 'पोन्नियिन सेल्वन : 2' के निर्माताओं से 'वीरा राजा वीरा...' गाने के क्रेडिट' में डागरवानी परंपरा के योगदान को मान्यता देने के लिए कहा था। उस्ताद फैयाजुद्दीन डागर के बेटे और उस्ताद जहीरुद्दीन डागर के भतीजे फैयाज वसीफुद्दीन डागर ने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी थी कि जूनियर डागर बंधुओं की सभी मूल रचनाओं (जिनमें 'शिव स्तुति' भी शामिल है) पर उनका कॉपीराइट है, जिसका उल्लंघन किया गया है।

डिजिटल रूप में भी पढ़ें दक्षिण भारत हिन्दी दैनिक www.dakshinbharat.com

फोटो : अभिषेक पोरवाल

श्रद्धा और भक्ति का उत्सव है गुरुमंदिर पंचाह्निका प्रतिष्ठा महोत्सव : आचार्य देवेन्द्रसागरसूरी

दक्षिण शांतिसूरी तीर्थ अरसीकेरे में संपन्न हुए 18 अभिषेक, 108 जोड़ों द्वारा गुरुपद पूजन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अरसीकेरे। स्थानीय योगीराज विजयशांतिसूरी मंदिर ट्रस्ट अरसीकेरे के तत्वावधान में दक्षिण शांतिसूरी तीर्थ परिसर में आचार्यश्री देवेंद्रसागरसूरीश्वर की निश्रा तथा आचार्यश्री अभयसेनसूरीश्वर के सान्निध्य में शुक्रवार को पांच दिवसीय योगीराज विजयशांतिसूरी गुरुमंदिर पंचाह्निका प्रतिष्ठा महोत्सव में 18 अभिषेक, ध्वज दंड अभिषेक, स्वर्ण कलश अभिषेक, मंगल मूर्ति अभिषेक, सुघोष घंट अभिषेक आदि विधि विधान संपन्न हुए। इस मौके पर आचार्य देवेंद्रसागरसूरीश्वरजी ने कहा कि यह पंचाह्निका महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक भावनाओं का उत्सव है। योगीराज का जीवन त्याग, तप और संयम का प्रतीक है। उनका जीवन धर्म प्रभावना और जीवों के कल्याण के लिए समर्पित रहा। यह महोत्सव सभी के जीवन में शांति, समृद्धि और आत्मकल्याण का कारण बने। आचार्य अभयसेनसूरीश्वर ने श्रद्धालुओं को धर्म आराधना में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।

कार्यक्रम में विशेष आमंत्रित शिवमोग्गा के सांसद बीवाई राघवेंद्र येड्डीयुरप्पा ने प्रतिष्ठा महोत्सव में उपस्थित होकर तीर्थ के दिव्य वातावरण की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहाँ आकर वे स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं। प्रतिष्ठा महोत्सव स्वागत समिति के अध्यक्ष कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन एवं अरसीकेरे विधायक शिवलिंगे गौड़ा ने सांसद एवं अन्य अतिथियों का स्वागत किया। सिरोही के मनोजकुमार बाबूमल हरण के मार्गदर्शन में हो रहे प्रतिष्ठा महोत्सव में विधि-विधान गौरव जैन एवं योगेश जैन द्वारा संपन्न कराए गए। नित्य पूजन गोविन्द रामलाल एण्ड पार्टी घाणेराव द्वारा करवाई जा रही है। दोपहर में 108 जोड़ों द्वारा शांतिसूरी गुरुपद पूजा संपन्न हुई। मंदिर की सुरम्य सजावट, रंगोली, शहनाई, एवं बैंड धूम जैन दोस्ती फेडरेशन की ओर से की गई।

द्वितीय दिन नाश्ता के लाभार्थी भेरूलाल मनोजकुमार परिवार, सुबह की नवकारसी के लाभार्थी अशोककुमार विजयकुमार कमलेशकुमार सुराना परिवार, शाम की नवकारसी के लाभार्थी रतनचंद गौतमचंद प्रकाशचंद सुंदेशा मुथा परिवार, 108 जोड़ों से गुरुपद पूजन लाभार्थी इंद्रकुमार दिनेश योगेश परमार परिवार, भक्ति एवं आरती के लाभार्थी जयंतीलाल संजय हितेश गुंदेशा परिवार, आंगी एवं रोशनी के लाभार्थी नेमीचंद दिलीप राजेश छाजेड़ परिवार टिपटूर आदि लाभार्थियों का तिलक लगाकर, माला, साफा, चुंदड़ी पहनाकर, श्रीफल, एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर मनीष हरण, अशोककुमार सुराना, जैन दोस्ती फेडरेशन, मोहनलाल बलदोटा, मनोजकुमार बाफना, धनराज गुलेच्छा एवं मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टीगण द्वारा किया गया।ङ्कङ्कप्रतिष्ठा महोत्सव समिति के चेयरमैन धीरज बच्छावत एवं प्रधान संयोजक गौतमचंद गुगलिया ने बताया कि रात्रि भक्ति संध्या में रायपुर के प्रसिद्ध गायक अंकित लोढ़ा एवं बेंगलूरु के जॉय सोलंकी के साथ भक्ति संध्या संयोजक दिलखुश बाफना ने भजनों की प्रस्तुति दी।

चेयरमैन ताराचंद राठौड़ एवं महासचिव विजयकुमार सुराना ने महोत्सव के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में श्री विजय शांतिसूरि मंदिर ट्रस्ट के दोनों उपाध्यक्ष विनोद मुणोत, ललित चोरड़िया रायपुर, कोषाध्यक्ष चेतन झारमुथा, सह कोषाध्यक्ष महावीरचंद चुत्तर, सचिव रमेश कटारिया, सह सचिव मांगीलाल मेहता, ट्रस्टीगण शांतिलाल नाहर, रमेशचंद परमार हासन, दुर्लभचंद खांटेड़, दानमल नाहर, दक्षिण नाकोड़ा तीर्थ के संस्थापक अध्यक्ष अशोककुमार सुराना, ट्रस्टी पारसमल वेदमुथा, मनोहरलाल सुराना बेंगलूरु महावीरचंद पंचाणुसा बोहरा बाणावर सहित मैसूर, तुमकुर, चिकमगलूर, कडूर, हासन, बेंगलूरु आदि स्थानों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। शनिवार को प्रातः योगीराज शांतिसूरीजी का विशाल वरघोड़ा निकाला जाएगा तथा रविवार को प्रतिष्ठा होगी। सोमवार को द्वारोद्घाटन होगा।

महिलाओं की उद्यमिता, सशक्तिकरण के लिए 'केनरा उत्सव 2026' कल से

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। केनरा बैंक दो दिवसीय प्रदर्शनी 'केनरा उत्सव 2026' का आयोजन करेगा, जो उद्यमिता और कला को बढ़ावा देने के साथ-साथ महिलाओं और स्थानीय कारीगरों को सशक्त बनाने का भी एक उद्देश्य है।

यह कार्यक्रम 22 और 23 फरवरी को जयमहल कन्वेंशन हॉल, जयमहल रोड, में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक आयोजित किया जाएगा। अपनी स्थापना से ही, महिला सशक्तिकरण कैनरा बैंक का प्रमुख उद्देश्य और प्रतिबद्धता रही है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक विकास के तहत, कैनरा बैंक विभिन्न स्थानों पर कैनारा उत्सव का आयोजन करके महिला उद्यमियों और कुशल कारीगरों को उनके कौशल का प्रदर्शन करने और उनके हस्तनिर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करके उनका समर्थन करना जारी रखता है।

इस प्रदर्शनी में जैविक खाद्य पदार्थ, मिट्टी के बर्तन, मिठाइयाँ, हस्तनिर्मित आभूषण, मोमबत्तियाँ और कई अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएँ प्रदर्शित की जाएँगी। आगंतुक आयोजन स्थल पर स्थित लाइव पॉटरी और मेहंदी काउंटरों पर प्रत्यक्ष अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं।

वर्ष 2021 के एक मामले में पुलिस पर चाकू से हमला करने के दोषी को सात साल का कठोर कारावास

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। बेंगलूरु की एक अदालत ने 2021 के हत्या के प्रयास के मामले में एक व्यक्ति को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उसपर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी मोहम्मद सलीम पुलिसकर्मियों पर हुए गंभीर हमले में शामिल था। पुलिस आयुक्त कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है, आरोपी के हेन्नूर सिग्नल से नागवारा की ओर रिंग रोड के सर्विस रोड पर एक कार में यात्रा करने के संबंध में मिली विश्वसनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने एचबीआर लेआउट स्थित वन कार्यालय के पास वाहन को रोका। इसके बाद आरोपी ने भागने की कोशिश की और अपने पास मौजूद चाकू से पुलिसकर्मियों पर हमला किया।

पुलिस ने बताया कि हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 24 जून 2021 को गोविंदपुरा थाने में मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि तत्कालीन डीसीपी (पूर्वी संभाग) शरणप्पा एस डी के निर्देशन में की गई जांच के दौरान डीजे हल्ली थाने के निरीक्षक किरण कुमार बी नायक ने सबूत एकत्र किए और एक विस्तृत आरोपपत्र दाखिल किया। बयान में आगे कहा गया है, मुकदमे की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उसे सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

देवी उत्सव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेंगलूरु के आदिशक्ति चामुंडेश्वरी देवस्थान सोण्णनहल्ली द्वारा बेंगलूर नगर देवता श्री अण्णम्मादेवी उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महेंद्र मुणोत ने देवी मां के दर्शन कर आशीर्वाद लिया एवं अन्नदान कार्यक्रम में सेवा प्रदान की। देवस्थान के जयराम एवं क्षेत्र के नागरिकों ने मुणोत का सम्मान किया।

बेंगलूरु दौरे पर आए नीदरलैंड के प्रधानमंत्री को विदाई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ 19 फरवरी की रात को बेंगलूरु की यात्रा के लिए बेंगलूरु पहुंचे।

नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने आर.टी. नगर स्थित फिलिप्स इनोवेशन कैंपस, इन्फैंट्री रोड पर स्थित बैंगलोर ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल सेंटर (बीटीपी कंट्रोल सेंटर), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) का दौरा किया और फिर होटल फोर सीजन्स में बेंगलूरु के व्यापारियों के साथ दोपहर के भोजन पर बैठक की। इसके बाद वे बेंगलूरु के केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे से विशेष विमान से एम्स्टर्डम के लिए रवाना हुए।

उन्हें सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने हार्दिक विदाई दी। इस अवसर पर सरकार की मुख्य सचिव डॉ. शालिनी रजनीश, बेंगलूरु शहर के पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव के.जी. जगदीश, बेंगलूरु ग्रामीण उप आयुक्त ए.बी. बसवराजु, बेंगलूरु क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.